स्वदेशी पत्रिका

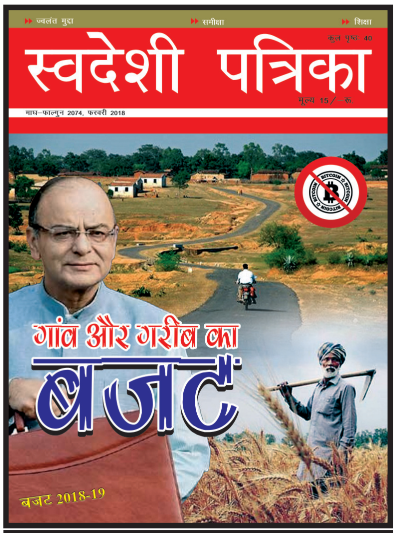

वर्ष–26, अंक–2

माघ–फाल्गुन 2074, फरवरी 2018

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

अ नु क्र म

आवरण कथा – पृष्ठ–6

गांव और गरीब का बजट

डॉ. अश्वनी महाजन

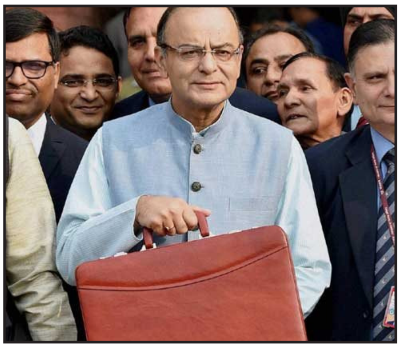

1 मुख्य पृष्ठ

2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

11 बहस
स्वावलम्बनः किसानों के संकट और कर्ज से मुक्ति का मार्ग .... डॉ. वंदना शिवा

14 विचार
आसियान के माध्यम से चीन को चुनौती .... दुलीचन्द रमन

17 विमर्श
वित्तीय घाटा बढ़ने दीजिये .... डॉ. भरत झुनझुनवाला

19 मुद्दा
मोदी–बेंजामिन दोस्ती के नये क्षितिज .... निरंकार सिंह

21 कृषि
कृषि व्यवस्था टिकाऊ और न्यायसंगत हो .... भारत डोगरा

24 चर्चा
पलायन और बेरोजगारी का दंश झेलता उत्तराखण्ड .... आशीष रावत

26 शिक्षा
वैदिक जीवन पद्धति से अनुप्राणित हो शिक्षा .... डॉ. रेखा भट्ट

29 विवरण
संविधान से ही होता है स्वतंत्रता का अहसास .... सूर्यप्रकाश अग्रवाल

31 ज्वलंत मुद्दा
डॉक्टरी पेशे की प्रतिष्ठा पर संकट .... अरूण तिवारी

38
स्वदेशी उत्पादनों की सूची

पाठकनामा/उन्होंने कहा 4

समाचार परिक्रमा 33-37

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**

चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

पाठकनामा

बंद हो डॉक्टरेट का अपमान!

एक अंग्रेजी अखबार ने देश में चल रही पीएच.डी. (डॉक्टरेट) की उपाधियों की हेरा–फेरी पर एक खोजपूर्ण खबर छापी है। देश के लगभग सभी विश्वविद्यालय ऐसे लोगों को भी मानद पीएच.डी. की डिग्री दे देते हैं, जिनके मैट्रिक पास होने का भी पता नहीं हैं। पिछले 20 साल में 160 विश्वविद्यालयों ने 2000 से ज्यादा लोगों को मानद डॉक्टरेट की उपाधियां बांटी हैं। ऐसी मानद डिग्री पानेवालों में देश के राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कई मंत्री तो हैं ही, सरकारी अफसर, कई अनपढ़ पूंजीपति और कई तथाकथित समाजसेवी भी हैं। इस मामले में मेरा कहना यह है कि ये सब लोग किसी न किसी कारण सम्मान पाने के हकदार हो सकते हैं लेकिन इन्हें डॉक्टरेट (पीएच.डी.) की डिग्री ही क्यों दी जाए। यह डॉक्टरेट या डी लिट की डिग्री का दुरुपयोग है। उस डिग्री का अपमान है। किसी भी विषय में डॉक्टरेट करने के लिए पांच–सात साल शोध करना पड़ता है। मैंने स्वयं जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में डॉक्टरेट की उपाधि के लिए शोध किया तो लगातार पांच साल सुबह 8 बजे से रात आठ बजे तक बैठकर पुस्तकालयों में काम किया। अंग्रेजी के अलावा तीन विदेशी भाषाएं सीखीं। सैकड़ों विदेशी नेताओं और विद्वानों से वार्तालाप किया। चार देशों में रहकर गहरा अनुसंधान किया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विख्यात विशेषज्ञों ने उसे स्वीकार किया। तब जाकर (जेएनयू) ने मुझे डॉक्टरेट की उपाधि दी। आप जिस विषय पर डॉक्टरेट करते हैं, उस विषय के पंडित ही नहीं, महापंडित माने जाते हैं जबकि मानद डॉक्टरेट पानेवाले कुछ लोग तो विद्वानों के बीच बैठने लायक भी नहीं होते। कुछ ऐसे भी लोगों को डॉक्टरेट दे दी जाती है, जिनसे उन विश्वविद्यालयों को आर्थिक लाभ हुआ हो या होने की संभावना हो। उन पर हुई तरह–तरह की कृपाओं को लौटाने का यह प्रमुख साधन बन गया है। इसके पीछे वे विश्वविद्यालय अपनी कमियों, धांधलियों और भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल देते हैं। कुछ लोग पैसे के जोर पर ये मानद उपाधियां या फर्जी डिग्रियां भी हथिया लेते हैं। वे अपने नाम के पहले 'डॉक्टर' लगाना कभी नहीं भूलते। उनके सारे नौकर–चाकर उन्हें 'डॉक्टर साहब' कहकर ही बुलाते हैं। मैं तो सर्वोच्च न्यायालय से कहता हूं कि ऐसी मानद और फर्जी उपाधियों पर वह कड़ा प्रतिबंध लगा दे ताकि हमारे विश्वविद्यालय बदनाम होने से बच सकें। इस तरह की उपाधियां और पद्मश्री और पद्मभूषण– जैसे सम्मान पानेवाले अपने निजी मित्रों को मैं प्रायः सहानुभूति का पत्र लिख देता हूं, क्योंकि इन कागजी उपाधियों के लिए उन्हें पता नहीं, किस–किस के आगे नाक रगड़नी पड़ती है।

डॉ. वेदप्रताप वैदिक, *ईमेल द्वारा*

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के जरिये आज हम लड़कियों की सुरक्षा-संरक्षा तथा शिक्षा की बात कर रहे है, पर सदियों पहले स्कंद पुराण में जिक्र है कि एक बेटी दस बेटों के बराबर है।

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

दुनिया में उभरती ताकत के रूप में चिन्हित भारत और इजरायल की दोस्ती से सुरक्षा, व्यापार, अर्थतंत्र और पर्यटन के क्षेत्र में दोनों देशों को महत्वपूर्ण लाभ होगा।

बेंजेमिन नेतान्हू
प्रधानमंत्री, इजरायल

सरकार बिट-कॉयन को विधिक मान्यता नहीं देती तथा इसके प्रयोग को रोकने के लिए हर संभव उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अरुण जेटली
वित्तमंत्री, भारत

संरक्षणवाद और संतप्ति वैश्विक रूझान है। भारत नये बाजारों की पहचान करने और अर्थव्यवस्था का विस्तार करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

सुरेश प्रभु
वाणिज्य मंत्री, भारत

सं
पा
द
की
य

एफएसएसएआई के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की साझेदारी चिंताजनक

भारत के खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की साठ–गांठ का मुद्दा स्वदेशी जागरण मंच ने उठाया है। विदेशी कंपनियों के हित में प्राधिकरण द्वारा बनाये गये कायदे कानूनों को खारिज करने की मांग करते हुए मंच ने कहा है कि विदेशी कंपनियां शिशु आहार के मामले में हस्तक्षेप कर रही हैं, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। कुछ साल पहले खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 'डाइट फॉर लाइफ' नामक एक परियोजना को आरंभ किया था, जिसके प्रमुख साझेदारों में से एक यंग एंड इन्फैंट न्यूट्रीशन कांउसिल ऑफ इंडिया भी है। तथ्य यह है कि चार अग्रणी बेबी फूड कंपनियों (जिसमें एबोट, नेस्ले, डॉनोन और मिड जोनशन शामिल है) ने एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के रूप में शिशु और युवा बाल पोषण परिषद (आई.वाई.एन.सी.आई.) शुरू किया है। ये कंपनियां दावा करती है कि डाइट फॉर लाईफ उनकी अपनी परियोजना है, लेकिन सब जानते है कि खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की सहमति के बगैर यह संभव नहीं है। ये विदेशी कंपनियां हमारे शिशु स्वास्थ्य में उतनी दिलचस्पी नहीं रखती, जितना कि इनका ध्यान अपने मुनाफे पर होता है। भारत के खाद्य सुरक्षा नियामक कार्यालय को स्पष्ट रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच ने इसे संस्थागत हित का संघर्ष करार देते हुए विरोध का स्वर बढ़ाया है। हाल के वर्षों में इस साझेदारी परियोजना का विकास हुआ है, इसके चलते राष्ट्रीय नीति को कम करके देखा जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। विशेष उद्देश्यों के लिए खाद्य पदार्थों तक पहुंच प्रदान करने के अपने उद्देश्यों के नाम पर बेबी फूड कंपनियों ने अपने व्यवसायिक हितों को बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो कि नीतिगत तौर पर भी उचित नहीं है तथा आईएमएस अधिनियम के तहत निषिद्ध भी है।

दिसंबर 2017 में गुरूग्राम के लेमन ट्री होटल में राष्ट्रीय नियोनोलॉजी फोरम द्वारा नेशनल कान्फेरेंश का आयोजन किया गया। एबोट और डैनोन इसके मुख्य प्रायोजक थे। आयोजकों ने दावा किया कि शिशु मिल्क विकल्प उत्पादों के क्षेत्र में उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के लिए सरकार से अनुमति मिली है। मालूम हो कि स्तनपान कराने की रक्षा हेतु पूर्व में शिशु दुग्ध विकल्प (आईएमएस) कानून बनाया गया था, जिसके चलते इन कंपनियों और इनके जैसे बेबी खाद्य निर्माताओं पर अंकुश लगाया गया था। आईएमएस अधिनियम धारा 9 की उपधारा 1 स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय प्रलोभन पर प्रतिबंध लगाता है। वित्तीय प्रलोभन का उल्लेख किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर सरकार ने अनुमति दी है तो क्या सरकार को कटघरे में खड़ा किया जायेगा? अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया है तो क्या आयोजक कंपनियों ने झूठी गवाही दी है, जो कि एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

भारत में स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाये गये है। ऐसे में शिशु और युवा बाल पोषण परिषद द्वारा सरकार की नाक के नीचे कंपनियों द्वारा चिकित्सकों का सम्मेलन आयोजित करना कहां तक जायज है। सभी बेबी फूड कंपनियां अपने शेयर धारकों के लिए पैसा कमा रही है। स्वास्थ्य प्रणाली का लक्ष्य हासिल करना उनकी प्राथमिकता नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था में सेंध लगाने के लिए जहां इन कंपनियों ने स्तनपान को कमजोर करने और उनके उत्पादन को व्यवस्थित रूप से स्वास्थ्य कार्मियों (डाक्टरों) के साथ अपने संबंधों में वृद्धि करने के लिए साठ–गांठ की है। डाईट फॉर लाइफ की प्रमुख साझेदार बेबी फूड कंपनियां एफएसएसएआई और नियोनोटोलाजी फोरम यह कहते हैं कि इस गतिविधि का उद्देश्य विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य के उपयोग को बढ़ावा देना है। इन कंपनियां का कहना है कि भारत में ऐसे पदार्थों की कमी है। इसलिए उन बच्चों को जिन्हें मरने का खतरा है उसे दिया जाना चाहिए। इस परिभाषा को प्रभावित करने के लिए एफएसएसएआई द्वारा एक अशोभनीय प्रयास किया गया है और चार प्रमुख शिशु खाद्य निगमों नेस्ले, एबोट, डानोन, मीड जॉनसन के साथ मिलजुलकर आईएमएस अधिनियम के प्रावधानों से कुछ विशेष खाद्य पदार्थों को मुक्त कर दिया गया है। इनबार्न एरर मेटोबोलिज्म (आईईएम) के लिए उत्पादों के आयात के रूप में यह कानून के तहत अनुमति है, वास्तव में एफएसएसएआई का मूल उद्देश्य इन कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए एफएसएमपी प्रावधानों के पालन में छूट प्रदान करना है। स्वदेशी जागरण मंच एसएसएफएआई की व्याख्या से कतई सहमत नहीं है कि एफएसएमपी शिशु के दूध के विकल्प नहीं है और यह भी मानना है कि एफएमएसएआई के पास आईएमएस अधिनियम के तहत परिभाषाओं को बदलने का जनादेश नहीं है।

स्वदेशी जागरण मंच के स्पष्ट किया है कि आईईएम मरीजों द्वारा उपयोग के लिए उत्पादों के आयात पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम आईएमएस अधिनियम के कार्यान्यवन का समर्थन करते हैं और शिशु मिल्क सब्सिटयूट की परिभाषाओं का पालन करने की मांग करते हैं। भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने भी एफएसएसएआई के विनियामक और प्रशासनिक ढ़ांचे के बारे में सवाल खड़े किये हैं।

गांव और गरीब का बजट

इस बजट में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य रक्षक योजना (ओबामा केयर से भी बड़ी), भाजपा के चुनाव घोषणा–पत्र के अनुरूप किसानों को उनकी सभी फसलों के लागत मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक का न्यूनतम समर्थन मूल्य, तीन साल तक सभी क्षेत्र के नए कर्मचारियों के भविष्य निधि में 12 प्रतिशत का सरकारी अनुदान, सब्जी उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकारी मदद सहित तमाम ऐसे उपाय हैं जो इसे पिछले कई वर्षों के बजट से अलग दिखाते हैं। मोदी सरकार का अंतिम 'पूर्ण बजट', गांव और गरीब के लिए समर्पित बजट कहा जाएगा।

10 करोड़ परिवारों के लिए यानी लगभग 50 करोड़ लोगों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य रक्षक योजना शुरू करने की घोषणा गरीबों के लिए एक बड़ी राहत का सबब बन सकती है

– डॉ. अश्वनी महाजन

मध्य वर्ग है थोड़ा निराश

हालांकि नौकरीपेशा लोगों के आयकर के रूप में बड़े सहयोग को वित्तमंत्री ने बजट में रेखांकित करते हुए कहा कि गैर–नौकरीपेशा लोगों से यह औसतन भी और कुल भी तीन गुना ज्यादा है, तो भी उन्हें टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं मिलने से वे थोड़े निराश दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बावजूद वे इस बात से जरूर राहत महसूस कर रहे होंगे कि कम–से–कम मानक कटौती के सिद्धांत को, जिसे काफी समय पहले खारिज कर दिया गया था, पुनः लागू किया गया है और नौकरीपेशा लोगों की आमदनी में 40 हजार रुपये की मानक कटौती लागू की गई है, जिससे उन्हें अधिकतम 12 हजार रुपये से अधिक का सालाना लाभ हो सकता है। इसी प्रकार 50 हजार रुपये तक के ब्याज को भी कर–मुक्त करने की घोषणा मध्यम वर्ग को राहत देने वाली है।

किसान को प्रसन्न करने वाला बजट

शायद किसान को भी इस बात की आशा नहीं थी कि भाजपा के चुनाव घोषणा–पत्र

के अनुरूप वित्तमंत्री लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत जोड़कर समर्थन मूल्य देने की घोषणा इस बजट में कर देंगे। इस बात की तो उन्हें कतई आशा नहीं थी कि सरकार इस समर्थन मूल्य को सभी फसलों पर लागू करने को सैद्धांतिक स्वीकृति दे देगी। ये दोनों बातें इस बजट में संभव हो पाईं, यह वास्तव में किसानों को प्रसन्न करेगा। गौरतलब है कि सरकारी तंत्र के लोग भी इस वायदे को लागू करने संबंधी बात करने से कतराया करते थे।

किसानों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अन्य भूमिहीन, जो खेती नहीं करते, लेकिन मत्स्य पालन, पशुपालन जैसी गतिविधियों में संलग्न हैं, कल्पना नहीं करते थे कि उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में कभी कृषि ऋण मिल पाएगा। अब वे किसान क्रेडिट कार्ड के हकदार बन जाएंगे। यह उनके लिए एक स्वप्न सरीखी बात ही कही जाएगी। यह कदम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रसन्न ही नहीं करेगा, बल्कि गैर कृषि रोजगार के अवसरों में भी खासी वृद्धि करेगा।

रोजगार सृजन हेतु ठोस प्रयास

लंबे समय से ऐसा महसूस किया जा रहा था कि वर्तमान विकास का मॉडल रोजगार सृजन में असफल हो रहा है। निवेश के लिए तो तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी लेकिन रोजगार सृजन के लिए कोई छूट नहीं मिलती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से सरकार द्वारा अतिरिक्त रोजगार सृजन पर आयकर में छूट, वस्त्र और अन्य कुछ उद्योगों में अतिरिक्त रोजगार देने पर कर्मचारी भविष्य निधि में सहयोग वगैरह शुरू हुआ था। इस बजट में इसे और आगे बढ़ाते हुए अब सभी उद्योगों में अतिरिक्त रोजगार देने पर कर्मचारी भविष्य निधि में 12 प्रतिशत योगदान सरकार की ओर से दिया जाएगा, ऐसी घोषणा बजट में हुई है, जो स्वागत योग्य है।

वित्तमंत्री ने कॉरपोरेट जगत को भी फायदा पहुंचाया है और 50 करोड़ से 250 करोड़ रुपये तक की आमदनी वाली कंपनियों का टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया है।

यही नहीं लघु उद्योगों को वित्त एवं कौशल निर्माण में मदद समेत कई उपायों से प्रोत्साहन देने की बात हुई है जिससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अतिरिक्त अवसर बांस और बांस से बनी वस्तुओं के निर्माण, गैर कृषि ग्रामीण गतिविधियों को बढ़ावा सहित कई उपाय हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा सकते हैं।

गरीबों को स्वास्थ्य में राहत

लंबे समय से यह बात सिद्ध होती रही है कि गरीबों को स्वास्थ्य की सरकारी सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण उनकी निर्भरता निजी क्षेत्र के अस्पतालों पर बढ़ती जा रही है, जिसके चलते वे लगातार कर्ज के बोझ में दब रहे हैं। गरीबों को और गरीब करने में स्वास्थ्य संबंधी खर्चे प्रमुख कारण हैं। ऐसे में 10 करोड़ परिवारों के लिए यानी लगभग 50 करोड़ लोगों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य रक्षक योजना शुरू करने की घोषणा गरीबों के लिए एक बड़ी राहत का सबब बन सकती है, जिसके अनुसार सभी परिवारों को पांच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य खर्च संबंधी सहायता उपलब्ध होगी। देखना होगा कि यह कैसे लागू होती है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से इस योजना की घोषणा ही एक बहुत बड़ा कदम है, जिसे सराहा जाना चाहिए। यही नहीं टी.बी. के सभी मरीजों के लिए 500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि भी एक सराहनीय कदम है।

रखना होगा विदेशी कंपनियों को बाहर

हालांकि मोदी सरकार के कार्यकाल में कई नए क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को अनुमति दी गई है, जिसके चलते अर्थव्यवस्था पर विदेशी प्रभुत्व बढ़ रहा है। यही नहीं, विदेशी कंपनियों की शर्तों को मानते हुए पूर्व के प्रावधानों को भी बदला जा रहा है। हाल ही में सिंगल ब्रांड में 30 प्रतिशत की खरीद भारत से ही करने की शर्त को हटा लिया गया है। जिसका दुष्प्रभाव देश में मन्यूफैक्चरिंग और खासतौर पर मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर पड़ सकता है।

नई स्वास्थ्य रक्षा योजना के बारे में सरकार को ध्यान रखना होगा कि इसके लिए विदेशी बीमा कंपनियों को शामिल न किया जाए, ताकि देश का धन विदेशों में न जाए। वित्तमंत्री ने कॉरपोरेट जगत को भी फायदा पहुंचाया है और 50 करोड़ से 250 करोड़ रुपये तक की आमदनी वाली कंपनियों का टैक्स 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि इसका कारण अन्य देशों में कॉरपोरेट टैक्स का घटाया जाना बताया जा रहा है। ❑❑

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजीडीएवी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर और स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं)

बजट 2018 की खास बातें–

वित्तमंत्री अरूण जेटली द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए पेश किये गये आम बजट में आयकर में छूट का दायरा तो नहीं बढ़ा लेकिन देश के किसानों, गांव के गरीबों के लिए बहुत कुछ शामिल किया गया है। 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन तथा 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख का बीमा की घोषणा महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत है बजट की खास बातें–

● **छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना के तहत तीन लाख करोड़ का प्रावधानः** वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने गरीबों के अलावा उद्योगों के लिए भी कई अहम ऐलान किए। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सरकार ने 6 हजार करोड़ का प्रावधान किया। वहीं बजट में छोटे और मझौले उद्योगों के लिए सरकार ने अलग से 3994 करोड़ का प्रावधान किया।

● **70 लाख नई नौकरियां सृजन करने का किया ऐलानः** यूनियन बजट 2018 में 70 लाख नई नौकरियों के सृजन की घोषणा की गई है। रोजगार सृजन के ज्यादा मौके देने जाने पर धयान दिया जाएगा। टेक्सटाइल, लेबर और फुटवियर क्षेत्र में 50 लाख युवाओं को 2020 तक प्रशिक्षण दिए जाने की योजना है। आने वाले 3 साल में नए कर्मचारियों के ईपीएफ में 12 फीसद का योगदान देने की योजना है। ईपीएफ में महिलाओं का योगदान 12 से 8 फीसद करने का ऐलान किया गया। इसके अलावा महिलाओं की मेटर्निटी लीव को 12 सप्ताह से 26 सप्ताह किया गया ताकि महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद मिल सके।

● **बजट 2018 में अरुण जेटली ने दिया महिला सशक्तिकरण पर जोरः** उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने की बात कहते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया कि सरकार का ध्यान महिला सशक्तिकरण पर भी है। व्यापार शुरू करने के लिए मुद्रा योजना के तहत 76 फीसद कर्ज लेने वाली महिलाएं हैं। 2022 तक हर गरीब को घर देने का लक्ष्य है। शहरी क्षेत्रों में 37 लाख मकान बनाने को मंजूरी दी गई है।

● **जल्द सभी ट्रेनों में लगेंगे सीसीटीवी और वाई–फाईः** वित्तमंत्री अरुण जेटली साल 2018–19 का बजट पेश कर रहे हैं। बजट में रेलवे के लिए 148528 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। 5000 किलोमीटर तक का आमान परिवर्तन ब्राडगेज होगा। विद्युतीकरण के क्षेत्र में भी काम को आगे बढ़ाया है।

● **गरीबों के घर हो बिजली से रोशन, मोदी सरकार ने सौभाग्य योजना की शुरूः** वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी खुद गरीबों के लिए केस स्टडी हैं, इसलिए ये सरकार गरीबों और मध्यम वर्गों के लिए सबसे ज्यादा काम कर रही है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि उज्जवला योजना के तहत भले ही पांच करोड़ गरीब महिलाओं को घरेलू गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य था। मगर इस योजना को गरीबों ने हाथों–हाथ लिया। इसलिए अब सरकार ने आठ करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। वहीं गरीबों के घर भी बिजली से रोशन हों, इसके लिए मोदी सरकार ने सौभाग्य योजना शुरू की है। इस योजना के तहत चार करोड़ गरीब घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी।

● **कम हुआ कॉर्पोरेट टैक्स, आयकर में कोई बदलाव नहींः** वित्त मंत्री ने टैक्स में बड़ी राहत देते हुए कहा कि पिछले साल के मुकाबले इसे आगे बढ़ाते हुए जिन कंपनियों का टर्नओवर सालाना 250 करोड़ है उन्हें भी कॉर्पोरेट टैक्स में 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा। देश की 99 प्रतिशत बहुत छोटे, छोटे व मछोले उद्योगों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने आयकर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है।

● **पहली बार प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के लिए एक नीतिः** वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट आज पेश किया। इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऐलान किया गया। जेटली ने कहा कि अब प्री–नर्सरी से 12 वीं तक के लिए एक नीति बनेगी। अब तक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अलग–अलग नीति होती थी लेकिन अब इसे समग्र रूप से देखना चाहते हैं।

● **किसानों को तोहफा, कर्ज के लिए बजट से 11 लाख करोड़ः** संसद में बजट 2018 पेश करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया है कि चार साल पहले हमारी सरकार ने जो वादा किया था उसको सरकार ने पूरा करके दिखाया है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। एक समय में भ्रष्टाचार देश में हावी था लेकिन आज देश के नागरिक इमानदारी से जीवन निर्वाह कर रहे हैं।

महंगा	सस्ता
टीवी–मोबाइल, विदेशी मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रोनिक्स और फूड प्रोसेसर, एलसीडी–एलईडी–ओएलईडी टीवी के कलपुर्जे, कारें और मोटरसाइकिलें, फ्रूट जूस, परफ्यूम, जूते–चप्पल, चांदी और सोना, सब्जियां, सनस्क्रीन, सनटैन, मैनीक्यूर, पेडिक्यूर का सामान, डेंचर फिक्सेटिव पेस्ट और पाउडर, डेंटल फ्लॉस, शेविंग से पहले और बाद इस्तेमाल किए जाने वाली प्रसाधन सामग्रियां, डियोडोरेंट, स्नान का सामान, परफ्यूम वाले स्कंेट स्प्रे, टायलेट स्प्रे, ट्रक और बसों के रेडियल टायर, रेशमी कपड़े, हीरे, कृत्रिम आभूषण स्मार्ट घड़ियां–वियरएबल उपकरण, फर्नीचर, गद्दे, लैंप, हाथ और पॉकेट घड़ियां, ट्राइसाइकिल, स्कूटर, पेडल कार, पहिये वाले खिलौने, गुड़िया, आउटडोर खेलों, स्वीमिंग पूल में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, सिगरेट और अन्य लाइटर।	● एलएनजी, प्रिपेयर्ड लेदर, सिल्वर फॉयल ● पीओसी मशीनें ● फिंगर स्कैनर ● माइक्रो एटीएम ● आइरिस स्कैनर ● सौर बैटरी ● देश में तैयार हीरे ● ई–टिकट पर से सर्विस टैक्स कम किया गया. ● अप्रसंस्कृत काजू ● सौर टेंपर्ड शीशे ● कॉक्लीअर इम्प्लांट ● कच्चा माल ● एक्सेसरीज

● **देश में चलेगा दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्रामः** वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 2018–19 के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए बड़े ऐलान किए। सरकार 1200 करोड़ रुपए खर्च कर एक नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम शुरू करने जा रही है, जिसमें 10 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 'आयुष्मान भारत' प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। इसके तहत देशभर में 1.50 लाख हेल्थ सेंटर बनाकर दवा और जांच की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। कुल मिलाकर देश की 40 फीसदी यानी 50 करोड़ आबादी के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी।

- **स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 40,000 तक की छूट**
- **250 करोड़ तक के टर्नओवर पर कार्पोरेट टैक्स 25 फीसद**
- **एफवाई 19 के लिए विनिवेश लक्ष्य 80,000 करोड़**

● **आलू–प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च करेंगेः** संसद में बजट 2018 पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया है कि चार साल पहले हमारी सरकार ने जो वादा किया था उसको सरकार ने पूरा करके दिखाया है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। एक समय में भ्रष्टाचार देश में हावी था लेकिन आज देश के नागरिक इमानदारी से जीवन निर्वाह कर रहे हैं।

- एग्री एक्सपोर्ट में 10,000 करोड़ की क्षमता
- इस साल डायरेक्ट टैक्स 12.6 फीसद बढ़ा
- कृषि के लिए क्लस्टर विकास योजना लागू
- आने वाले वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करने पर फोकस
- ग्रोथ का फायदा किसानों को मिलेगा, गांव व बुजर्गों पर ध्यान
- 8.2 करोड़ लोगों ने डायरेक्ट टेक्स दिया
- फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रुपए
- 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे
- नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम आएगी
- एफवाई 18 का वित्तीय घाटा 3.5 फीसद रहेगा
- एफवाई 19 में वित्तीय घाटा 3.3 फीसद रहेगा
- नेशनल हेल्थ पॉलिसी के लिए 1200 करोड़
- 1 लाख पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ेंगे
- गांवों के लिए 5 लाख हॉट–स्पॉट
- स्मार्ट सिटी में 2350 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा
- 70 लाख नई नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य
- जनजातियों के विकास के लिए 32,000 करोड़ रुपए
- 50 लाख युवाओं को नौकरियों के लिए मिलेगी ट्रेनिंग
- गंगा सफाई के लिए 187 योजनाएं मंजूर
- 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख प्रतिवर्ष बीमा
- 2022 तक हर गरीब का अपना घर होगा
- प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के लिए 16,000 करोड़
- ऑपरेशन ग्रीन के लिए 5 हजार करोड़ आवंटित
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 42 अंकों का सुधार
- सर्विस सेक्टर में 8 फीसद से ज्यादा की ग्रोथ होगी
- 8 फीसद से ज्यादा जीडीपी हासिल होगी
- ईज ऑफ डूईंग बिजनस में 42 अंकों का सुधार
- लागत से डेढ़ गुना कीमत किसानों को मिल रही है
- गरीबों को दिया मुफ्त गैस कनेक्शन
- 800 से ज्यादा दवाईयां सस्ती दरों पर
- गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा एवं मध्य वर्ग के लिए आवास सेवाएं
- गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दे रही है सरकार ❑

बजट 2018–19

स्वच्छता अभियान पर जोर

– अनिल तिवारी

जब कोई समाज अपनी प्रचलित परंपराओं को भूलने लगता है, यानि कि आत्म–विस्मृति का शिकार हो जाता है तो उसे उन चीजों की याद दिलानी पड़ती है जो कभी उनके दैनिक दिनचर्या का अंग रही हो। देश में स्वच्छता को लेकर भी कमोवेश ऐसी ही धारणाएं काम करती रही है। भारत प्राचीनकाल से ही स्वच्छता के प्रति एक संवेदनशील समाज रहा है। स्वच्छता को अपने जीवन का अनिवार्य अंग मानकर चलने वाला भारत कभी–कभी विचलन का शिकार हुआ लेकिन शीघ्र ही इसने अपनी परंपरा को पहचाना तथा मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई।

एक मौके पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर मनु महाराज एक बार भारतवर्ष की धरती पर आयें तो यह देखकर वे अत्यंत हर्षित होंगे कि भारत तमाम आक्रमणों, विदेशी हमलों और झंझावातों के बावजूद अपने मूल्यों को खासकर स्वच्छता के सिद्धांतों और आदर्शों को ज्यों–का–त्यों संयोए रखा है।

मालूम हो कि भारतीय समाज अपने उद्भव से ही एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज के रूप में अपनी पहचान दर्ज कराता रहा है। स्वच्छता यहां के दैनिक दिनचर्या का हिस्सा रही है। ब्रह्ममूहर्त में बिस्तर त्याग, तत्काल बाद शौच के लिए जाना, शौच से आकर हाथ–पैर धोना, फिर दंत धावन, स्नान, जुते–चप्पल उतारकर रसोईघर में जाना, कपड़े उतारकर चोके में खाना–खाना, अनिवार्य रूप से लागू किया जाता रहा है। वहीं महिलाएं प्रातः बिस्तर त्याग के बाद प्रथम कार्य के रूप में हाथ में झाड़ू लेकर घर–बाहर साफ करना, घर–बाहर की गऊ–गोबर से लिपाई करना, चोके

में अतिरिक्त स्वच्छता बनाये रखना अपना पुनीत कर्तव्य समझती रही है।

देश में अंग्रेजों के आगमन के बाद स्वच्छता के मोर्चे पर विचलन बढ़ी। अंग्रेजों ने जहां मलमूत्र त्याग के लिए पाश्चात्य तरीके अखतियार किये वहीं उनकी देखा–देखी भारत के लोगों में भी कुछ आलस देखा गया। महात्मा गांधी पहली बार इसे पहचाना तथा इस पर व्यापक विमर्श कर काम शुरू किया। गांधी जी ने स्वच्छता को लेकर समाज में व्याप्त लिंग भेद और जाति भेद को भी उजागर किया। गांधी जी के इस प्रयास को हालांकि उतनी सफलता नहीं मिली, जितना उन्होंने या उनके जैसे लोगों ने अपेक्ष की थी, परंतु मौटे तोर पर गांधी जी ने तीन विषयों पर गंभीर बहस चलाने का सफल प्रयास किया।

पहला– स्वच्छता में लिंग भेद और जाति भेद को सिरे से खारिज करने का। गांधी जी ने खुद हाथ में झाड़ू उठाया, घर–बाहर साफ किया, बर्तन धोए, कपड़े धोए। गांधी जी ने कहा कि घर में बच्चें साफ–सुधरा करने से लेकर बर्तन धोने तक की जिम्मेवारी केवल औरते ही क्यों उठायें, पुरूष क्यों नहीं? इसी तरह अस्पृश्य जातियों को मूलधारा में शामिल करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। गांधी जी का मानना था कि जो लोग मल–मूत्र साफ करने के काम में लगे है उन्हें विशिष्ठ व्यक्ति का दर्जा दिया जाना चाहिए तथा उन्हें इस बात के लिए पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए।

दूसरा– तकनीक के स्तर पर गांधी जी ने स्थानीयता को आगे कर वर्धा शौचालय की शुरूआत की। उनका मानना था कि अंग्रेज बहादुर मल–मूत्र साफ करने के नाम पर लाखों टन पानी की बर्बादी करते हैं तथा यह गंदगी भरा जल हमारे नदियों और नहरों को भी प्रदूषित कर रहा है। गांधी जी की अपील को लोगों ने हाथों–हाथ लिया और वर्धा शौचालय जल्दी ही देश दुनिया के गाधीवादियों के बीच फैल गया।

तीसरा– गांधी जी गंदगी के लिए आधुनिकीकरण और महाकाय नगरों के निर्माण को जिम्मेवाद मानते थे। उनका कहना था कि आखिर गांव को नष्ट कर शहर क्यों बढ़ाये जा रहे हैं। शहरों को निर्माण औद्योगिकीकरण के लिए हो रहा है लेकिन यह हमारे स्वच्छ समाज को एक गंदे समाज में परिवर्तित करने का कारण भी बन रहा है।

2 अक्टूबर 2014 को केंद्र की एनडीए सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर स्वच्छता अभियान को शुरू किया है। खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार प्रतिबद्ध दिख रही है। इस बजट में भी शौचालय के लिए अतिरिक्त धन का इंतजाम किया गया है। वित्तमंत्री ने बताया कि जब एनडीए की सरकार सत्तारूढ़ हुई तब देश में 36 प्रतिशत लोगों को शौचालय की सुविधा थी। महज 3 साल की छोटी अवधि में अब 78 प्रतिशत लोगों को शौचालय उपलब्ध है। सरकार ने बजट 2018 में 2 करोड़ नये शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा है।

स्वावलम्बनः किसानों के संकट और कर्ज से मुक्ति का मार्ग

गतांक से आगे...

भारत सरकार एक बार फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में आकर आयात में कटौती के नाम पर जीएमओ सरसों के लिए बाध्य होती दिख रही है।

फर्जी दालों का आयात और भ्रष्टाचारः दालें हमारी धरती, हमारे खेत और हमारे जीवन की धड़कन हैं। दालें हमारे खेतों को नत्रजन देती हैं। हमारी प्राचीन कृषि–संस्कृति में मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने की सभी बातें सम्मिलित है, जिसमें दालों को विशेष महत्व दिया गया है। कृषि विविधता पर एकल खेती ने जो कहर बरपाया, दालें उसके प्रभाव में सीधे आ गई। गहन रसायनों को बढ़ावा देने वाली हरित क्रांति के कारण सह–फसली खेती असंभव हो गई। इस कारण से खेतों में दालों की बुवाई कम हो गई और स्वाभाविक तौर पर उनका उत्पादन घट गया। दलहनी फसलें खेत की मिट्टी में नत्रजन का संतुलन करती हैं, जिसकी वजह से दूसरी फसलों की पैदावार में भी बढ़ोत्तरी होती है।

हम गेहूं और धान की एकल खेती के कारण दलहनी फसलों से वंचित हो गये। 1960–61 और 2010–2011 के मध्य गेहूं की पैदावार 29.58 प्रतिशत से 44.5 प्रतिशत, धान 4.79 प्रातिशत से 25 प्रतिशत हो गई, ठीक इसी समय दालें 19 प्रतिशत से 0.21 प्रतिशत, तिलहन 3.9 प्रतिशत से 0.71 प्रतिशत, मोटे अनाज 11.26 प्रतिशत से 0.21 प्रतिशत हो गई। दालें 150 से 200 किलो/हे. नत्रजन का स्थिरीकरण करती हैं। जबसे खेतों से दलहनी फसलों को उगाना छोड़ दिया, तब से कृत्रिम नत्रजन का प्रयोग को बढ़ावा मिला है।

दालें हमारी धरती, हमारे खेत और हमारे जीवन की धड़कन हैं। हमारी प्राचीन कषि–संस्कति में मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने की सभी बातें सम्मिलित है, जिसमें दालों को विशेष महत्व दिया गया है।

– डॉ. वंदना शिवा

पुस्तक 'सॉयल नॉट ऑयल' स्पष्ट करती है कि किस तरह से औद्योगिक कृषि ने जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देकर वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाने में 40 प्रतिशत से अधिक योगदान देती है। यह योगदान कार्बनडाइऑक्साइड से 300 गुना अधिक है। ये ग्रीन हाउस गैसे जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। कृत्रिम नत्रजन जीवाश्म ईंधन से बनाई जाती है। हिटलर के समय में घटित द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस तरह की नत्रजन को अमोनियम नाइट्रेट के रूप में विस्फोटक बनाने हेतु प्रयोग में लाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब बड़ी मात्रा में यह विस्फोटक बच गया, तो उसका प्रयोग खेतों में नत्रजन हेतु किया जाने लगा। प्राकृतिक नत्रजन को कृत्रिम नत्रजन बनाने के लिए उच्च तापमान पर गर्म करके अमोनिया प्राप्त की जाती है। अमोनिया सभी तरह के कृत्रिम नत्रजन उर्वरकों के लिए फीडस्टोक है, जो विस्फोटक का काम भी करता है। एक किलोग्राम कृत्रिम नत्रजन बनाने के लिए दो–लीटर डीजल की खपत होती है।

हरित क्रांति ने एकल खेती के माध्यम से खेतों में दालों की बुवाई नगण्य कर दी, और अब बीटी कपास और सोया के कारण दलहन और तिलहन हाशिये पर चले गये हैं। 2014 में 11.6 लाख हेक्टेयर जमीन पर बीटी कपास लगाया गया, जबकि दलहन इसके आधे हिस्से

में ही उगाई गयीं, वहीं 12.12 लाख हेक्टेयर जमीन पर सोया उगाया गया। इस पूरे क्षेत्र पर पहले दाले ही उगती थी। इस तरह से हम 10 लाख हेक्टेयर पर दाल नहीं उगा पा रहे हैं और भारत में दालों की कृत्रिम कमी बनाई जा रही है। इस कमी को दूर करने के नाम पर दालों का आयात करके आम आदमी की पहुंच से उसे दूर किया जा रहा है। 2015 में एक किलो अरहर के दाम 200 रूपये तक पहुंच गए।

पीली मटरः 2012 में कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दाल के नाम पर पीली मटर का आयात किया जा रहा है। भारतीय भोजन प्रणाली को ध्यान में न रखते हुए सरकार ने 2007 में पीली दालों का आयात किया। जब इन दालों का कोई खरीदार न मिला तो इन्हें लंबे विलंब के साथ बहुत कम कीमत पर बेचा गया, जिससे आयात करने वाली एजेंसी को बड़ा घाटा सहना पड़ा। 2009 में इन एजेंसियों को 1,201.32 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा, लेकिन यह घाटा यहीं तक सीमित नहीं रहा।

पीली मटर के आयात से जहां लोगों को पोषण की कमी हुई, वहीं खेतों के स्वास्थ्य में भी गिरावट आई। 2015–16 में सरकार ने अमेरिका तथा कनाडा से 50 लाख टन पीली दाल आयात करने की योजना बनाई। पीली दाल में मात्र 7.5 प्रतिशत प्रोटीन होता है, वहीं देशी दाल में यह मात्रा 20–30 प्रतिशत होती है। इस तरह से देखा जाए तो आयात की गई 5 लाख टन की जगह पर देश में उत्पन्न 1 लाख टन दाल ही प्रयाप्त थी। इससे हमारे खेतों को एक अरब किलो नत्रजन की प्राप्ति होती।

2017 में दालों का भरपूर उत्पादन हुआ, लेकिन सरकार ने किसानों के साथ किये गये वादे नहीं निभाये। वाजिफ समर्थन मूल्य पर दालें नहीं खरीदी। मध्य प्रदेश में 60 प्रतिशत दालें बिक नहीं पाई, जिससे कृषि संकट गहरा गया और किसान नाराज हो गये। ज्ञात हो कि जून 2016 में सरकार ने तुअर और मूंग पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 425 रूपये बोनस देने की घोषणा की थी।

हुआ यूं कि सरकार फसल कटाई के समय पर चूक कर गई, वहीं बंपर पैदावार किसानों के लिए संकट में बदल गई। दूसरी तरफ बंपर पैदावार के बावजूद दालों का आयात बंद नहीं किया गया। इस तरह से सरकार किसानों को न्याय देने की बजाय निगमों के हितों को साधने पर लग गई। 2017 के वित वर्ष

आजादी का रास्ता बीज स्वराज और बीज संप्रभुता से होकर जाता है, इसके लिए जीएमओ सरसों सहित सभी तरह के जीएमओ पर रोक लगनी चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीज पर सब्सिडी देना बंद किया जाना चाहिए।

में दालों का आयात 19.9 प्रतिशत से बढ़कर 56 मिलियन टन हो गया।

कृषि संकट से निपटने और किसान की खुशहाली का विकल्प है स्वावलम्बनः कृषि संकट को रोकने का त्वरित तरीका है कर्ज से मुक्ति। सरकार द्वारा कॉर्पोरेट कृषि को बढ़ावा देने के कारण ही किसानों पर अत्यधिक कर्ज बढ़ गया। सरकार की कॉर्पोरेट कृषि नीति के चलते ही किसान कर्जे के लिए विवश हो जाता है। जब से सरकार ने कॉर्पोरेट नियंत्रण की नीति अपनाई, तब से किसान संकट से जूझ रहे हैं। किसानों का ऋण माफ किया जाना चाहिए और किसी भी तरह के नए कर्ज यथा कॉर्पोरेट बाजार, कॉर्पोरेट बीमा, जलवायु परिवर्तन अथवा मिट्टी के आंकणों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खरीदने से बचाया जाना चाहिए। 2017 में किसानों ने पर्याप्त दालों का उत्पादन किया। फर्जी पीली दाल को आयात करने के बजाय, किसानों से दाल खरीदी जानी चाहिए थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव के चलते सरकार किसानों का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य देने से बचती रही। हमारी नीति देश को आत्मनिर्भरता और संप्रभुता बढ़ाने वाली होनी चाहिए।

बीज पर नया उपनिवेशवाद बंद होः नई आजादी का रास्ता बीज स्वराज और बीज संप्रभुता से होकर जाता है, इसके लिए जीएमओ सरसों सहित सभी तरह के जीएमओ पर रोक लगनी चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीज पर सब्सिडी देना बंद किया जाना चाहिए। और अनुच्छेद–3ज की रक्षा की जानी चाहिए। मोनसेंटो के कारण होने वाली किसानो की आत्महत्या और आर्थिक नुकसान की भरपाई मोंनसेंटो के द्वारा ही की जानी चाहिए। पूरे देश में किसानों के द्वारा चलाये जा रहे सामुदायिक बीज बैंको का पंजीकरण अनिवार्य करने हेतु नया बीज कानून बनाया जाना चाहिए। विकासवादी पादप प्रजनन हेतु किसान–वैज्ञानिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

कॉर्पोरेट जगत हमारी खेती को रसायनों और जहरों के माध्यम से उपनिवेश बना रहे हैं, उनके द्वारा यह मिथक फैलाया जा रहा है कि पारिस्थितिक खेती के माध्यम से पर्याप्त भोजन का उत्पादन करना सम्भव नहीं है और छोटे किसान अच्छे उत्पादक नहीं है। किसानों को ऐसे भ्रमों से दूर रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम अपनाना चाहिए।

कृषि बने जहर मुक्त, स्वस्थ और पोषणयुक्तः नवधान्य के माध्यम

से इन तीन दशकों के मध्य किये गये हमारे कार्य यह सिद्ध करते हैं कि जहर–मुक्त और पारिस्थितिकी आधारित खेती से हम भारत जैसे दो–देशों के लिए के लिए पोषणयुक्त अन्न का उत्पादन (हेल्थ पर एकड़) कर सकते हैं।

विविधता स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें कटौती नहीं की जा सकतीः छोटे किसान विषविहीन और पोषणयुक्त भोजन विविधता के उत्पादक हैं। वे हमारे वैद्य हैं, क्योंकि वे हमें अन्न उत्पन्न करके स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के महंगे उत्पादों को खरीदने से बचाया जाये। इन कंपनियों के महंगे रसायनिक उर्वरक, कीटनाशक और बीज खरीदकर किसान कर्ज में डूब जाते हैं। भोजन का वस्तुकरण नहीं किया जा सकता। पेप्सी जैसी कंपनियां किसानों (उदाहरण के लिए बंगाल के आलू उत्पादक किसान) से एक फसली खेती करवाती हैं और उन्हें बहुत ही सस्ते दामों पर उत्पाद बेचने के लिए मजबूर करती हैं।

नवधान्य का अनुभव बताता है कि जब किसान अपने बीजों पर ही निर्भर रहते हैं और पारस्थितिक खेती करते हैं तो उनकी आय 10 से 100 गुना बढ़ (हेल्थ पर एकड़) जाती है।

छोटे खेत और छोटे किसानों को बचाया जाएः छोटे किसान बढ़े किसानों से कहीं अधिक उत्पादन करते हैं। नवधान्य का 1 एकड़ माड़ल फार्म अनाज, सब्जी, चारा और औषधीय पौध के उत्पादन के साथ 4 लाख रूपये वार्षिक की कमाई देता है। भारत छोटे किसानो की भूमि है। छोटे किसान 1 अरब 30 करोड़ भारतीयों को पोषित कर सकते हैं। छोटे किसान ही सच्चे अन्नदाता हैं। आज हमारा अन्नदाता किसान कर्जे के जाल में फंस गये हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भूमण्डलीकरण, आर्थिक नव–उदारवाद के माध्यम से बीज और भोजन के प्रति गुलामी ढ़ाने का काम किया है। इस कारण से 1995 से अब तक 300,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

भूमण्डलीकरण का मिथक है कि छोटे किसान अनुत्पादक (उत्पादक न होना) होते हैं और उनकी खेती को बड़ी औद्योगिक खेती में बदल देना चाहिए। यह बात वैज्ञानिक दृष्टि से झूठी और समाजिक दृष्टि से अन्यायपूर्ण है। सभी वैज्ञानिक साक्ष्य सिद्ध करते हैं कि छोटे खेत बड़े खेतों की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होते हैं। जैसे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री चौधरी चरण सिंह ने कहा था–''कृषि एक जीवन प्रक्रिया बन रही है, वास्तविक कृषि कार्यों की दृष्टि से देखा जाए तो खेतों के बढ़ते हुए आकार के अनुपात में उनसे कम पैदावार होती है (दूसरे शब्दों में, खेतों पर लगने वाला मानव श्रम और देखरेख की दृष्टि से उनसे उत्पादन प्रति एकड़ कम होता है)। यदि भारत जैसे घने आबादी वाले देश में एक व्यक्ति को 100 एकड़ जमीन और अन्य चालीस व्यक्तियों को 2.5 एकड़ जमीन पर कार्य करने का विकल्प दिया जाए, तो छोटे फार्म पर बहुत कम लागत लगेगी।''

विश्वभर में छोटे किसानों के द्वारा 25 प्रतिशत खेती योग्य भूमि से कुल 70 प्रतिशत उत्पादन होता है, वहीं औद्योगिक खेती में प्रयुक्त 75 जमीन से 30 प्रतिशत भोजन पैदा किया जाता है। बड़े खेत जहां 75 प्रतिशत मिट्टी, पानी, जैवविविधता को नष्ट करते हैं, वहीं 50 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से वायुमण्डल को प्रदूषित कर जलवायु को अस्थितर करते हैं।

औद्योगिक खेत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, भोजन का नहीं। इस माध्यम से उगाया जाने वाली 98 प्रतिशत मक्का को जैव ईंधन और पशु–आहार के लिए प्रयोग लिया जाता है। ऐसी खेती में कुल उत्पादन की अपेक्षा अत्पादन लागत कहीं अधिक आती है। ऐसी खेती बिना सब्सिडी के नहीं हो सकती।

छोटे किसान जैवविविध, पारिस्थिक तथा बिना जहर वाला असली भोजन उगाते हैं। बड़े किसान गहन रसायन, सघन मशीनीकरण पर आधारित एकल खेती करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े फायदे के लिए किसानों को अपने मंहगे उत्पादों को खरीदने के लिए मजबूर कर देती हैं, किसानों का कर्ज में फंसने का यह भी एक बडा कारण है। मोनसेंटो क्लाइमेट डाटा कॉर्परेशन के माध्यम से किसान को क्लाइमेट के आंकडे और बीमा बेचकर उसे और भी कर्जे में फंसाने और अपनी आय बढ़ाने की प्रक्रिया में है। मोनसेंटो का बीमा बजार 3 खरब अमेरिकन डॉलर का है। मोनसेंटो हमारी बीज और भोजन की स्वतंत्रता को नष्टकर बीज और भोजन के प्रति हमें गुलाम बना देना चाहता है।

बीज और भोजन की दासता के विरूद्ध नवधान्य ने सफलता के 30 साल पूर्ण किये, हमारा यह विरोध आगामी 30 सालों तक लगातार जारी रहेगा। हम अपने छोटे खेतों से स्वस्थ एवं जहर मुक्त भोजन उगाते रहते रहेंगे।

हम अपने देश में एक एकड़ खेत में गहन जैवविविधता और एक पारिस्थितिक खेती के बल पर खुशहाली लाने में कामयाब हो सकते हैं। रसायनिक खेती किसानों को कर्ज में धकेलकर आत्महत्या के लिए मजबूर कर देती है। कॉपोरेशन/बहुराष्ट्रीय कंपनियां बिचौलिया बनकर किसानों के उत्पाद पर 99 प्रतिशत तक लगान वसूल रहे हैं। वे औद्योगिक प्रसंस्करण के माध्यम से इन उत्पादों से और भी मुनाफा कमा लेते हैं। इस तरह से अन्नदाता और उपभोक्ता दोनों ही घाटे में रहते हैं, और सारा लाभ ये कॉर्पोरेशन ले लेते हैं। आज की आजादी की लड़ाई जहरीले गिरोहों से मुक्ति पाने के लिए है। ❑❑

(लेखिका प्रसिद्ध पर्यावरणविद, नोबल पुरस्कार के समानान्तर राईट लवलीहुड एवार्ड विजेता)

आसियान के माध्यम से चीन को चुनौती

इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह कुछ खास रहा क्योंकि इस वर्ष 69वें गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान आसियान के दस देशों (म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस और ब्रुनेई) के सर्वोच्च नेता मुख्य अतिथि के रूप में नई–दिल्ली में उपस्थित रहे। यह गणतंत्र दिवस के इतिहास मे पहला मौका था जब एक साथ दस देशों के राष्ट्राध्यक्षों के गणतंत्र–दिवस परेड़ का मुख्य अतिथि के रूप में अवलोकन किया।

गणतंत्र–दिवस के अवसर पर किसी भी विदेशी मेहमान की मौजूदगी भारतीय विदेश–नीति की दिशा तय करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के गठन के बाद 2015 में अमेरिका के तात्कालिक राष्ट्रपति बराक ओबामा, 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसिसों होलन्दे 2017, मे संयुक्त अरब अमीरात के किंग मोहम्मद बिन जायेद उपस्थित रहे। इसी कड़ी मे 2018 में आसियान के शासनाध्यक्षों की मौजूदगी भारतीय विदेश नीति में आसियान के महत्व को रेखांकित करती है। यह भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' की दिशा में एक और कदम है।

पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय कुटनीति तथा भारत के पड़ोस में सामारिक परिदृश्य में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। अमरीका, चीन के दोनों मित्र देशों (उत्तर–कोरिया और पाकिस्तान) को आड़े हाथों ले चुका है। उत्तर–कोरिया के खिलाफ अमरीका व अन्य देशों द्वारा लगाये गये आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद चीन उसकी मदद करता आ रहा है। पाकिस्तान को लेकर भी नये साल की नई सुबह में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ज्ञान प्राप्त हुआ कि पाकिस्तान ने अमरीका से पिछले पंद्रह–बीस सालों में अरबों अमरीकी डालर की मदद लेकर भी अमरीका के साथ धोखा किया है। चीन ने तुरंत अपने चेले पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने के उसके ट्रेक–रिकार्ड को देखते हुए प्रशंसा–पत्र दे दिया। बदले में पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने पाकिस्तान में चीनी मुद्रा युवान को 'निवेश' व व्यापार में

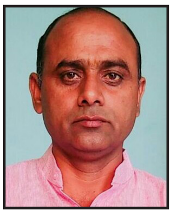

गणतंत्र दिवस के अवसर पर आसियान के शासनाध्यक्षों की मौजूदगी भारतीय विदेश नीति में आसियान के महत्व को रेखांकित करती है। यह भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' की दिशा में एक और कदम है।

– **दुलीचन्द रमन**

प्रचलन की आज्ञा दे दी। जो सीपैक के बाद चीनी चंगुल में जाने का एक और कदम है।

चीन की मंशा इस क्षेत्र में भारत को घेरने की रही है। भारत की बढ़ रही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा एशिया में चीनी चौधर के लिए खतरा लग रही है। यह सही है कि पिछले चालीस–पचास सालों से भारत–चीन सीमा पर अमूमन शांति रही है। लेकिन दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास की कमी रही है तथा स्थितियां शीत–युद्व जैसी बनी रही है। चीन ने भारत के पड़ोसी सार्क देशों के संबंधों में सेंध लगाने का भरसक प्रयास किया है जो कुछ–कुछ सफल भी रहा है।

हमारे चिर–मित्र पड़ोसी नेपाल में राजशाही के खात्में और उसके बाद गृहयुद्व के दिनों में वहां परिस्थितियों के पीछे अगर चीनी वामपंथी विचारधारा का हाथ रहा तो उसके बाद संविधान निमार्ण में भारतीय मूल के मधेशी समुदाय के हितों को लेकर भारत द्वारा की गई आर्थिक नाकेबंदी से स्थितियां लगातार चीन के पक्ष में होती चली गई। नेपाल में वामपंथी दलों का सत्ता में आना चीन को रास आ गया। फलस्वरूप नेपाल में सरकार चीनी कठपूतली की तरह काम कर रही है।

भूटान को लेकर भारतीय और चीनी सेनाएं डोकलाम क्षेत्र मे आमने–सामने डटी रही। 75 दिनों के बाद यह मुद्दा आंशिक रूप से सुलझा लिया गया क्योंकि चीनी कंम्यूनिस्ट पार्टी की 19वीं बैठक होनी थी। पिछले दिनों उपग्रह से प्राप्त चित्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि चीन अपने क्षेत्र में स्थायी सैन्य निर्माण कर रहा है जिससे भूटान सरकार पर अनावश्यक दबाव बढ़ने की संभावना है। क्योंकि इस क्षेत्र में पहले चीनी सेना पैट्रोलिंग हेतु आती थी तथा बाद में लौट जाती थी। भूटान की सुरक्षा को लेकर भारत अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन देर सवेर चीन भूटान के साथ अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित करने की कोशिश करेगा। इसके लिए वह सैन्य दबाव व आर्थिक निवेश का लालच दे सकता है।

सार्क का एक सदस्य पाकिस्तान पहले ही चीन के हाथों में खेल रहा है। अफगानिस्तान भी पिछले दिनों सीपैक के मसौदे पर कुछ-कुछ हिचक के साथ चीन की हाँ में हाँ मिला चुका है।

श्रीलंका में तमिल मुद्दे को लेकर भारत के साथ अविश्वास की स्थिति बनी। हमने परिस्थितियों को भांपते हुए भारतीय शांति सेना भेजी। लेकिन श्रीलंका में बहुसंख्यक सिहंली समुदाय और राजनीतिक नेतृत्व में भारत के प्रति अविश्वास के कारण चीन को वहां भी मौका मिल गया। आधारभूत संरचना और आर्थिक विकास व निवेश के नाम पर हब्बनटोटा जैसी अव्यवहारिक व गैर लाभप्रद बंदरगाह के नाम पर निवेश के माध्यम से श्रीलंका की सरकार को अपने ऋणजाल में फंसा लिया। श्रीलंका ने इस बंदरगाह को 99 साल के पट्टे पर चीन को सौंपकर अपना ऋण बोझ तो हल्का कर दिया लेकिन भारत के लिए एक खतरे का बीज अपनी भूमि में रोंप दिया।

म्यांमार में पूर्व की लोकतंत्र विरोधी सैन्य सरकार के कार्यकाल के दौरान हमने कूटनीतिक पर्दा सा गिरा रखा था। इस दौरान चीन वहां भी अपना प्रभाव बढ़ा चुका था। वहां भी क्योकप्यू बंदरगाह के विकास के नाम पर म्यांमार सरकार पर चीनी कर्ज का बोझ बढ़ चुका है। रोहिग्या मसले में भी वह अपनी टांग अड़ाता रहता है। म्यांमार में सक्रिय सभी चरमपंथी गुटों को भी चीन ही मदद कर रहा है। म्यांमार भी आशा की दृष्टि से अब भारत की तरफ देख रहा है।

मलद्वीव में भी चीन भारत से बाजी मार ले गया। नवंबर 2017 के आखिरी सप्ताह में मालद्वीव की संसद ने चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लगा दी। एक समय था जब 1988 में भारत ने मालद्वीव में राष्ट्रपति अब्दुल गयूम की सरकार का तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम किया था। फिर वह समय भी आया जब वर्तमान राष्ट्रपति यामीन ने माले में अतंर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण में लगी भारतीय कंपनी के साथ समझौता तोड़कर उसे चीन की कंपनी को दे दिया।

सार्क का एक सदस्य पाकिस्तान पहले ही चीन के हाथों में खेल रहा है। अफगानिस्तान भी पिछले दिनों सीपैक के मसौदे पर कुछ–कुछ हिचक के साथ

चीन की हाँ में हाँ मिला चुका है।

दक्षिण एशिया में बढ़ता चीनी हस्तक्षेप भारतीय कुटनीति को संकुचित नही कर सकता। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी व विदेश मंत्रालय लगातार एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है। आसियान के देशों के राष्ट्राध्यक्षों का गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनना, इसी दिशा में एक कदम है। भारत और आसियान के देशों के बीच सदियों पुराने रिस्ते रहे है। ये संबंध इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए है। सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से रामायण और महात्मा बुद्व हमें एक–दूसरे के करीब लाते है।

आसियान देश भारत के साथ संवाद सांझेदारी के 25 साल पूरे कर चुके है। सिंगापुर और वियतनाम चाहते है कि एशिया–प्रशांत क्षेत्र में भारत की पैठ बढ़े, क्योंकि चीनी दखल से इस क्षेत्र में असुरक्षा का भाव है। वियतनाम, फिलिपिंस, मलेशिया और ब्रुर्नेई के साथ तो चीन का सीमा संबंधी विवाद है। फिलिपिंस दक्षिण चीन सागर के मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी जा चुका है जिसका फैसला चीन के खिलाफ आया हैं। वियतनाम के साथ भारत दक्षिण चीन सागर में तेल उत्पादन व रक्षा क्षेत्र में सहयोग कर रहा है। आसियान के सम्मेलन के दौरान 'समुद्री सुरक्षा और नौ परिवहन आजादी' पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान के 6 राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। जिससे इस आसियान सम्मेलन का महत्व और भी बढ़ गया है।

हिन्द–प्रशांत क्षेत्र ने भारत, अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया की संयुक्त नौसैनिक अभ्यास से आसियान के देशों में चीनी आक्रमकता का डर कम किया जा सकता है। यह बात सही है कि विदेश–नीति की गुणा–भाग कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार करता है। चीन वर्तमान में आर्थिक निवेश और तकनीकी कुशलता का मुखौटा लगाकर विश्व में अपने हित साध रहा है। दुनिया–भर मे रेल लाईनों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के निर्माण के लिए तीसरी दुनिया के ज्यादातर देश उसकी सेवायें ले रहे है। चीन निवेश को हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा है जिससे वह संबंधित देश की नीतियों को प्रभावित करने की स्थिति में पहुंच जाता है।

आर्थिक रूप से सुदृढ़ भारत ही क्षेत्रीय तथा वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान बना सकता है, इसके लिए अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार, उच्च आर्थिक विकास तथा घरेलू मोर्च पर कृषि और रोजगार जैसे विशयों पर ध्यान देने की दरकार है।

हमें सार्क, आसियान, अफ्रीकी संघ, जी–20 तथा दूसरे मंचों पर सभी परिस्थितियों में निरंतर प्रयास करने होंगे ताकि भारत के हितों की रक्षा की जा सके। 21वीं सदी एशिया के साथ–साथ भारत की सदी बन सके। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

वित्तीय घाटा बढ़ने दीजिये

वित्तमंत्री ने आगामी वर्ष के बजट में वित्तीय घाटे पर नियंत्रण रखने का क्रम जारी रखा है। वर्ष 2013—14 में सरकार का वित्तीय घाटा देश की आय का 4.5 प्रतिशत था। चालू वर्ष 2017—2018 में यह 3.5 रह गया है। आगामी वर्ष में इसे और घटाकर 3.2 प्रतिशत पर लाने की योजना है। वित्तीय घाटे पर नियंत्रण करने का मंत्र अस्सी के दशक में विश्व बैंक ने दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में बनाया था। उस महाद्वीप की कई सरकारें अति भ्रष्ट थीं। उनके नेता विश्व बैंक से ऋण लेकर, रकम का रिसाव कराकर, स्विस बैंक के अपने व्यक्तिगत खातों में जमा करा रहे थे। तब विश्व बैंक ने मंत्र बनाया कि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को निजी निवेश के आधार पर बढ़ाया जाये। निजी निवेशकों के द्वारा लाई गई रकम को मेजबान देश के नेता रिसाव कराकर गबन नहीं कर पायेंगे।

अगला प्रश्न था कि निजी निवेशकों को कैसे आकर्षित किया जाये? विश्व बैंक ऋण न दे तो भी मेजबान सरकार के नेता नोट छापकर रकम का गबन कर सकते थे। ऐसे में विदेशी निवेशकों को भरोसा नहीं बनता था इसलिये वित्तीय घाटे पर नियंत्रण का मंत्र बनाया गया। विश्व बैंक ने सलाह दी कि विकासशील देशों की सरकारें अपने वित्तीय घाटे पर नियंत्रण करें। वित्तीय घाटा कम होगा तो अर्थव्यवस्था स्थिर रहेगी और विदेशी निवेश आयेगा। ज्ञात हो कि वित्तीय घाटा वह रकम होती है जो सरकार ऋण लेती है। अपनी आय से अधिक खर्चों को सरकार इस रकम से पोषित करती है। वित्तीय घाटे पर नियंत्रण करने के लिये सरकार को अपने कुल खर्च कम करने होंगे। इन्हें कम करने को सरकार को निवेश भी कम करना होगा। इससे विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता था। परंतु विश्व बैंक ने कहा कि निजी विदेशी निवेश आयेगा और आर्थिक विकास सुचारू रूप से चलता रहेगा। अतः वित्तीय घाटे पर नियंत्रण करने के मंत्र के पीछे सोच थी कि मेजबान सरकार भ्रष्ट होने से सरकारी निवेश पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिये सरकारी निवेश घटाओ

वित्तमंत्री को चाहिये कि वित्तीय घाटा नियंत्रित करने के विश्व बैंक के मंत्र को त्याग दें, ऋण लेकर सरकारी निवेश बढ़ायें और देश को 15 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ायें।

- डॉ. भरत झुनझुनवाला

और निजी निवेश बढ़ाओ। वित्तमंत्री द्वारा विश्व बैंक के इसी मंत्र का अनुपालन किया जा रहा है। इसी दिशा में सरकार द्वारा मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। सोच है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश करेंगी और हमारी अर्थव्यवस्था चल निकलेगी।

अस्सी के दशक में जब वित्तीय घाटे का मंत्र बनाया गया था और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर है। उस समय बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन में फैक्ट्रियां लगा रही थीं चूंकि चीन में वेतन कम थे। आज चीन तथा भारत में वेतन बढ़ रहे हैं इसलिये सस्ते वेतन का आकर्षण कम हो गया है। । बीते दशक में आटोमेटिक मशीनों से उत्पादन होने लगा है। रोबोट द्वारा कार बनाई जा रही है। आज मैन्यूफैक्चरिंग में श्रम की जरूरत कम हो गयी है। तमाम फैक्ट्रियां विकासशील देशों से वापस यूरोप एवं अमरीका जा रही हैं चूंकि अब श्रम की जरूरत ही कम रह गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनी में 10,000 श्रमिक हों तो सस्ते वेतन का गहरा प्रभाव पड़ता है। उसी कंपनी में केवल 100 श्रमिक हों तो उन्हें अधिक वेतन देने का कम प्रभाव पड़ता है। इसलिये विदेशी निवेश भारत में नहीं आ रहा है। एक और कारण है कि वर्तमान समय में अमरीकी अर्थव्यवस्था में तकनीकी अविष्कार हो रहे हैं। वह अर्थव्यवस्था गतिमान है। वहां के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। विदेशी निवेशकों को अब अमरीका के सुरक्षित वातावरण में पर्याप्त आय मिल रही है इसलिये उनका भारत जैसे विकासशील देशों की तरफ रुझान कम हो गया है। रोबोट के उपयोग तथा अमरीका में ब्याज दर बढ़ने से विदेशी निवेशक भारत को कम ही आ रहे हैं।

इस परिस्थिति में वित्तमंत्री के सामने दो रास्ते खुले थे। एक रास्ता था कि सरकारी निवेश को नियंत्रण में रखते, वित्तीय घाटा कम बनाये रखते और विदेशी निवेश के भरोसे भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते। दूसरा रास्ता था कि सरकारी निवेश बढ़ाते, वित्तीय घाटा बढ़ने देने और घरेलू निवेश के सहारे अर्थव्यवस्था को बढ़ाते। वित्तमंत्री ने विश्व बैंक द्वारा बताये पहले रास्ते को चुना है। वित्तीय घाटे को कम करने का प्रयास जारी है, जैसा इस लेख के प्रारंभ में बताया गया है। परंतु यह रास्ता सफल नहीं है। विदेशी निवेश धीमी गति से ही आ रहा है। घरेलू निवेश भी कम हो रहा है चूंकि सरकार ने अपने खर्च कम कर रखे हैं। निवेश के दोनों स्त्रोत ढ़ीले पड़े हुये हैं। हमारी अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत की विकास दर पर ही अटकी हुयी है। 15 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने की तो चर्चा भी नहीं हो रही है।

वित्तमंत्री को वित्तीय घाटे पर नियंत्रण करने के विश्व बैंक के मंत्र को त्यागकर घरेलू निवेश बढ़ाना चाहिये था। वर्तमान एनडीए सरकार मूल रूप से ईमानदार है।

वित्तमंत्री को वित्तीय घाटे पर नियंत्रण करने के विश्व बैंक के मंत्र को त्यागकर घरेलू निवेश बढ़ाना चाहिये था। वर्तमान एनडीए सरकार मूल रूप से ईमानदार है। विदेशी और घरेलू निवेश दोनों में सुस्ती के बावजूद हमारी विकास दर 7 प्रतिशत की दर पर है चूंकि वर्तमान सरकार ने सरकारी रकम के रिसाव पर लगाम लगाई है। इस परिस्थिति में ऋण लेकर निवेश करना चाहिये था। उद्यमी के लिये बैंक से ऋण लेकर फैक्ट्री लगाना अच्छा माना जाता है। फैक्ट्री द्वारा अर्जित रकम से ऋण को अदा किया जा सकता है। लेकिन शराबी द्वारा पड़ोसी से ऋण लेना अच्छा नहीं माना जाता चूंकि लिये गये ऋण को वह अदा नहीं कर पाता है। इसी प्रकार सरकार बाजार से ऋण लेकर हाइवे एवं एयरपोर्ट में निवेश करे तो अच्छा है। हाइवे बनने से अर्थव्यवस्था में गति आयेगी, सरकार को टैक्स अधिक मिलेगा और लिये गये ऋण को अदा किया जा सकेगा।

आज दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। वर्तमान 7 प्रतिशत विकास दर विश्व के प्रमुख देशों में अधिकतम हो तो भी बात नहीं बनती है। नब्बे के दशक में चीन ने 13 प्रतिशत की विकास दर हासिल की थी। आज हमारा लक्ष्य 15 प्रतिशत विकास दर हासिल करने का होना चाहिये।

सरकार को विश्व बैंक के मंत्र से उबरना चाहिये। विश्व बैंक पर मूल रूप से अमरीकी सरकार का वर्चस्व है। अमरीकी सरकार पर अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व है। ये कंपनियां चाहती हैं कि विकासशील देशों की सरकारें स्वयं ऋण लेकर निवेश न करें जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश करने एवं लाभ कमाने का खुला मैदान मिल जाये। लेकिन इस समय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में निवेश पसंद नहीं आ रहा है चूंकि रोबोट ने अमरीका में निवेश करना लाभप्रद बना दिया है और अमरीकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। इस प्रकार हम पर दोहरी मार पड़ रही है। विदेशी और घरेलू दोनों ही निवेश ढ़ीले पड़े हुये हैं और हम 7 प्रतिशत की विकास दर पर अटके हुये हैं। वित्तमंत्री को चाहिये कि वित्तीय घाटा नियंत्रित करने के विश्व बैंक के मंत्र को त्याग दें, ऋण लेकर सरकारी निवेश बढ़ायें और देश को 15 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ायें। ❑❑

(लेखक आईआईएम के पूर्व प्राध्यापक, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री व स्तंभकार हैं।)

मोदी-बेंजामिन दोस्ती के नये क्षितिज

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर आये। मोदी के इजराइल दौरे के सिर्फ छह महीने बाद ही यह किसी इजरायली प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। दोनों देशों की दोस्ती नया इतिहास लिख रही है। भारत और इजराइल के बीच परस्पर सहयोग के नौ करारों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें साइबर, सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, हवाई यातायात से लेकर होम्योपैथिक उपचार और अक्षय ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में सहयोग के समझौते शामिल हैं। हालांकि भारत और इजराइल के बीच व्यापारिक रिश्ते पुराने हैं। भारत हर साल करीब एक अरब रूपये का प्रतिरक्षा साजो–सामान इजराइल से खरीदता है। परंतु पिछले दिनों दो ऐसी घटनाएं घटी थीं जिससे यह संदेह हुआ कि कहीं दोनों देशों के बीच ठंडापन न आ जाये। पहली घटना थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यरूशलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के फैसले के खिलाफ भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में मतदान और दूसरी, नेतन्याहू की यात्रा से कुछ ही दिन पहले एंटी टैंक मिसाइल का करार रद्द होना। अच्छी बात है कि इजराइल ने इन्हें दोस्ती के आड़े नहीं आने दिया। नेतन्याहू ने कहा कि भारत के संयुक्त राष्ट्र में वोट देने से दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते रिश्तों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला।

अच्छी बात है कि इजराइल ने इन्हें दोस्ती के आड़े नहीं आने दिया। नेतन्याहू ने कहा कि भारत के संयुक्त राष्ट्र में वोट देने से दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते रिश्तों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला।

– **निरंकार सिंह**

दरअसल भारत जैसे समर्थ राष्ट्र की मैत्री विश्व स्तर पर इजराइल की स्वीकृति को भी और बढ़ाती है। फिलस्तीन के मामले को भारत इलराइल संबंधों में अलग रखा गया है क्योंकि भारत इजराइल और सहयोग परिषद (जीसीसी) के छह देशों अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन और कुवैत के साथ रिश्ते मजबूत रखना चाहता है। रक्षा और कृषि की दृष्टि से इजराइल की दोस्ती भारत के लिए लंबे समय से महत्वपूर्ण बनी हुई है। जल प्रबंधन, विज्ञान एवं तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करते आये हैं। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के चलते भारत में गंभीर जल संकट है। बढ़ती आबादी इसे बद से बदतर कर रही है। ऐसा कोई शहर नहीं हैं जहां सातों दिन चौबीस घंटे गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति होती हो। पानी संकट बारहमासी बनता जा रहा है। हमें इस हालात से उबारने में भारत का मित्र देश इजराइल मदद कर सकता है। दस वर्ष पहले भारत जैसी ही स्थिति इजराइल की भी थी। लेकिन जल प्रबंधन की प्रभावी तकनीकें अपनाकर उसने खुद को इस संकट से उबार लिया। दस वर्ष पहले इजराइल में पानी का घोर संकट था। ऐसे में इस देश ने दोहरी रणनीति अपनाई। पहले तो पानी की बर्बादी को रोका और फिर पानी सप्लाई के स्रोतों में इजाफा किया। ऐसा करके अब इजराइल भरपूर जल संसाधन वाला देश बन गया। अब चीन, जापान और कनाडा जैसे देश इजराइल से उसकी तकनीक मांग रहे हैं।

इंडो–इजराइली एग्रीकल्चरल को–आपरेशन प्रोजेक्ट के तहत इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय विकास सहभागिता एजेंसी माशव और भारत के राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बीच करार हुआ। इस सहयोग के चलते भारतीय किसान 65 फीसदी कम पानी के इस्तेमाल में 10 गुना अधिक पैदावार करने में सक्षम हुए। इस प्रोजेक्ट को बड़े स्तर पर अपनाकर एक बड़े भूजल को बचाया जा सकता है। खारे पानी को पेयजल में बदलने के मामले में इजराइल दुनिया का अग्रणी देश है। ऐसे प्लांट भारत में पहले से हैं, लेकिन इजराइली तकनीक कहीं ज्यादा उन्नत है। इजराइल ने ऐसा संयंत्र तैयार किया है जो गंदे खारे पानी को पेयजल में बदल सकता है। इस संयंत्र से लैस गाड़ियां भारत के ग्रामीण इलाकों में बेहद कम दाम पर पानी मुहैया करा सकती है।

इजराइल ने हवा से पानी बनाने की तकनीक पर भी विशेषज्ञता हासिल कर ली है। सौर ऊर्जा का प्रयोग करके यहां हवा की नमी से पीने का पानी बनाया जाता है। भारत और इजराइल दोनों ही हीरा और रक्षा सौदों से आगे आर्थिक संबंध बनाने की दिशा में हैं। 2016–17 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 5.02 अरब डॉलर था जिसमें रक्षा सौदा (अनुमानित सालाना 60 करोड़ डॉलर) नहीं था। कच्चा, गैर–औद्योगिक हीरों का आयात–निर्यात एक अरब डॉलर से ज्यादा रहा था। नेतन्याहू के 100 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, रक्षा और प्रौद्योगिकी की कंपनियों के प्रतिनिधि होंगे। पिछले साल जून में उनकी कैबिनेट भारत में गैर हीरा निर्यात को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने और आरऐंडडी के लिए 4 करोड़ डॉलर खर्च करने पर राजी हो गई थी। प्रस्तावों में बॉलीवुड को इजराइल में शूटिंग के लिए सुविधाएं देने और ढेरों भारतीय कंपनियों को व्यापार के लिए बढ़ावा देना शामिल था।

लेकिन यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन होगा। कृषि, जल और समुद्री जल से नमक अलग करने की प्रौद्योगिकी जिसमें इजराइली एक बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है, कई कारणों से बड़ी चुनौती साबित होगी जैसे कि लागत और किसानों को छोटी खेतिहर जमीनें। भारत के किसानों के लिए समुद्री पानी से नमक अलग करने और लघु सिंचाई की प्रौद्योगिकी महंगी हो सकती है लेकिन पानी और बिजली सस्ती है क्योंकि उन्हें भारी सब्सिडी दी जाती है। इसीलिए भारत इजराइली रक्षा संबंध वृद्धि का सबसे फायदेमंद क्षेत्र है। जिसमें सरकार ही ग्राहक है। इजराइल भारत का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा हार्डवेयर आपूर्तिकर्ता है जो 2012 और 2016 के बीच देश के हथियार आयात का 7.2 प्रतिशत था। इसमें रडार, मिसाइलें, युद्ध के इलेक्ट्रानिक उपकरण सिस्टम और बम शामिल थे। इजराइल के रक्षा निर्यात में भारत का हिस्सा 40 प्रतिशत से भी ज्यादा है जिसमें उसे सालाना करीब एक अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा की कमाई होती है।

1948 में इजराइल मरूभूमि था। आज भी उसका काफी बड़ा भाग रेगिस्तान ही है। वर्षों तक यहाँ के निवासियों ने पानी की अत्यधिक कमी के कारण बड़ी पीड़ाएं और कष्ट सहे। लेकिन कड़ी और सतत मेहनत की बदौलत और उन्नत प्रौद्योगिकी के सहारे इजराइलियों ने इस निर्जल, बंजर और सूखी भूमि को एक बड़ा उद्यान में बदल दिया हैं। उस आधुनिक तकनीक में महारत हासिल कर रखी है इजराइलियों ने जिसके द्वारा ये बंजर भूमि को जलमय कर सकते हैं।, गंदे पानी के एक स्रोत को नष्ट होने से बचाने के लिए उसको स्वच्छ कर पुनः चकित कर सकते हैं। पानी के जंग लगे पाइपों को चमकाकर दुबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं और पानी की विशालतम मात्रा को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला सकते हैं। उनके वैज्ञानिक जल के संभावित स्रोत का पता लगा लेते हैं। वे यूरोप के अधिक उपजाऊ देशों के उन लोगों के लिए जो खुद मेहनत करके भाजियां और फल उत्पन्न करते हैं।

इजराइल का अनुमान है कि दो दशकों के बाद मध्य पूर्व की जनसंख्या दुगुनी हो जायेगी। तब इस क्षेत्र की पानी की मांग बढ़कर दुगुनी होगी। इजराइल इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है, अपने साधनों द्वारा पर्यावरण तथा विकास के मुद्दों पर राष्ट्र संघ की जून 1992 की 'रियो घोषणा' जो संघ द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है, सब सरकारों और राष्ट्रों की विश्व स्तर पर साझेदारी से पर्यावरण की रक्षा की जायेगी। इस घोषणा में कहा गया है, ''शांति, विकास और पर्यावरण की रक्षा अविभाज्य है तथा एक दूसरे पर आश्रित मुददा है। इजराइल ने तभी से इस घोषणा के अनुरूप कार्य करना आरंभ कर दिया था। एक राष्ट्र के रूप में वह विकास के जिस स्तर तक पहुंच चुका है, उससे भारत बहुत कुछ सीख सकता है।

भविष्य में किसी राष्ट्र की शक्ति उसकी वित्तीय स्थिति पर कम, उसकी मानसिक शक्तियों के बाहुल्य पर अधिक निर्भर करेगी। इस कसौटी पर यदि सब राष्ट्रों को कसा जाए तो इजराइल इक्कीसवीं सदी में अपनी मानसिक शक्तियों की अधिकता के कारण सरलता से अपनी समस्याओं का समाधान कर रहा है। इस छोटे से देश में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले आठ विश्वविद्यालय है, जो प्रतिभाशाली युवक–युवतियों की खान हैं। इजराइल में शत–प्रतिशत साक्षरता है। ❑❑

(लेखक हिन्दी विश्वकोश के सहायक संपादक रह चुके हैं। आज कल स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य कर रहे हैं।)

कृषि व्यवस्था टिकाऊ और न्यायसंगत हो

आज विश्व भर में खतरनाक रसायनों के दुष्परिणामों, जमीन के घटते उपजाऊपन भूजल के अत्यधिक दोहन जैसी समस्याओं की गंभीरता को देखते हुए एक ऐसी कृषि व खाद्य व्यवस्था की पड़ताल चल रही है जो टिकाऊ हो और जिससे पर्यावरण की तबाही न हो। तरह–तरह के विकल्प सामने आ भी रहे हैं, किन्तु कभी–कभी इन विकल्पों की तलाश में कृषि व्यवस्था को न्यायसंगत बनाने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना जरूरी है। इस कमी को दूर करना होगा तभी विकल्पों की यह तलाश सही अर्थों में आगे बढ़ पाएगी। एक ओर पर्यावरण का ध्यान रखना होगा व दूसरी ओर गरीब किसानों की जरूरतों का। इन दोनों तरह की सोच के मिलन से ही एक टिकाऊ व न्यायसंगत कृषि व्यवस्था निकल पाएगी। इस रास्ते की तलाश में हम परंपरागत तकनीक से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं व आज दुनिया के अनेक देशों में हो रहे नए प्रयासों से भी।

कृषि, पशुपालन, वानिकी, जल–प्रबंध, भवन–निर्माण और विभिन्न दस्तकारियों के क्षेत्र में जो परंपरागत ज्ञान उपलब्ध है, वह बहुमूल्य है। अलग–अलग क्षेत्र की जलवायु, भूमि, जल उपलब्धि और अन्य भौगोलिक विशेषताओं के अनुकूल आजीविका के क्या तरीके हो सकते हैं, बुनियादी जरूरतें प्राप्त करने के लिए क्या तकनीक अपनानी चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय किन सावधानियों और कैसे अनुशासन की आवश्यकता है, इस बारे में कई पीढ़ियों और शताब्दियों से संचित जो ज्ञान है उसकी अवहेलना तो मूर्खता होगी। जल्दबाजी और लालच में जब भी ऐसी मूर्खता की गई है तो शीघ्र ही उसके प्रतिकूल परिणाम सामने आए हैं।

परंपरागत तकनीक की एक विशेषता यह है कि मनुष्य में अपनी गलतियों से सीखने की जो क्षमता है, ऐसी अनेक शताब्दियों की क्षमता का उसमें संचय है। मनुष्य अपनी जरूरतें

कृषि, पशुपालन, वानिकी, जल–प्रबंध, भवन–निर्माण और विभिन्न दस्तकारियों के क्षेत्र में जो परंपरागत ज्ञान उपलब्ध है, वह बहुमूल्य है। अलग–अलग क्षेत्र की जलवायु, भूमि, जल उपलब्धि और अन्य भौगोलिक विशेषताओं के अनुकूल आजीविका के क्या तरीके हो सकते हैं।

– भारत डोगरा

बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिए तरह–तरह के प्रयोग करता रहा। इनमें से जिनके उचित परिणाम नहीं मिले, उन्हें वह कुछ समय बाद छोड़ता रहा और लंबे समय तक जिनके अच्छे परिणाम मिले, उन्हें वह अधिक स्थाई तौर पर अपनाता रहा। इस प्रक्रिया में कई शताब्दियों के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, दस्तकारों आदि की अपने कार्य और हुनर के बारे में सोच, सुधार की संभावनाओं और सीमाओं के बारे में उनका दृष्टिकोण एकत्र हुआ है। इसकी उपेक्षा भला कैसे की जा सकती है?

तकनीक के बारे में हमें जो ज्ञान परंपरा से मिल सकता है, वह भी उन जगहों से अपेक्षाकृत कम मिलेगा जहां सामंती या जागीरदारी प्रवृत्तियां हावी थीं। जहां किसानों और कारीगरों का अपेक्षाकृत स्वतंत्र अस्तित्व था और अपनी आजीविका को बेहतर करने के साधन, समय और प्रोत्साहन उन्हें उपलब्ध था, वहां तकनीक के बेहतर होने की संभावना अधिक है। यह संभावना वहां भी अधिक है जहां मिलकर काम करने की संभावना अधिक है। इस दृष्टि से अनेक आदिवासी समाजों से सीखने की संभावना अधिक है।

यहां यह याद दिलाया जा सकता है कि हमारी सबसे महत्वपूर्ण फसल धान को आधुनिक समय में सुधारने के लिए कैम्ब्रिज से डाक्टरेट प्राप्त विख्यात कृषि वैज्ञानिक डा. आर. एच. रिछारिया को सबसे अधिक संभावना आदिवासी किसानों और उनकी कार्य पद्धति में मिली। प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण के बारे में भी अनेक आदिवासी समुदायों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है।

भारतीय संदर्भ में आज न्यायसंगत और टिकाऊ खेती के क्षेत्र में सबसे पहला कदम व्यापक स्तर पर भूमि–सुधार व भूमि पुनर्वितरण होना चाहिए जिससे भूमिहीन, गरीब व छोटे किसानों को अधिक भूमि मिल सके।

आज छोटी परियोजनाओं से जल संरक्षण व संग्रहण पर जोर देना चाहिए, तभी टिकाऊ सिंचाई प्राप्त होगी। इस प्रयास में छोटे व गरीब किसानों को सिंचाई उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।

इसके बाद मेड़बंदी व भू तथा जल संरक्षण के उपायों से इस भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। जहां तक संभव हो, जहां पानी गिरता हो वहीं उसे रोककर विशेषकर इन कमजोर वर्ग के किसानों के लिए सिंचाई का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उचित स्थान पर तालाब बनाए जा सकते हैं या जो टूट–फूट गए हैं, उनकी मरम्मत हो सकती है। छोटे चैक डैम बनाए जा सकते हैं। परंपरागत, स्थानीय भूगोल के अनुकूल विधियों जैसे दक्षिण बिहार व झारखंड की अहर–पाईन पद्धति के आधार पर प्रयास हो सकते हैं। ऐसे प्रयास सारे गांव, विशेषकर निर्धन वर्ग की भागीदारी से होने चाहिए व सरकार की विभिन्न संबंधित योजनाओं को यहां समग्रित किया जाना चाहिए।

आज सिंचाई व खेती के तौर–तरीकों के परंपरागत ज्ञान की व्यापक स्तर पर अवहेलना की जा रही है। सिंचाई के लिए बड़े बांधों के निर्माण व नहरों के जाल से व्यापक सामाजिक व पर्यावरणीय दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं–बड़े पैमाने पर विस्थापन, बहुत सी उपजाऊ भूमि खो देना या इसका दलदलीकरण व लवणीकरण, नदी के निचले क्षेत्र में पानी की कमी व कुंओं का सूखना, मछुआरों व मछलियों की तबाही आदि। दूसरी ओर टयूबवैलों द्वारा अत्यधिक पानी उलीचने के कारण भू–जल नीचे जाने की समस्या भी सामने आ रही है। इस अनुभव से सीखते हुए आज छोटी परियोजनाओं से जल संरक्षण व संग्रहण पर जोर देना चाहिए, तभी टिकाऊ सिंचाई प्राप्त होगी। इस प्रयास में छोटे व गरीब किसानों को सिंचाई उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।

वनों की रक्षा, वृक्षारोपण, चरागाहों की रक्षा करना व अधिक हरियाली लाना भी इतना ही जरूरी है। इसमें स्थानीय फल, चारे, भू व जल संरक्षण की दृष्टि से अच्छे समझे जाने वाले पेड़ों को प्राथमिकता मिले। जहां जल संरक्षण व हरियाली बनाए रखने पर ध्यान दिया जाएगा, वहां बिना रसायनिक खाद के

बिना भी अच्छी उत्पादकता प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध होंगे।

मिट्टी में विभिन्न पोषक तत्वों (जिनमें महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्व भी सम्मिलित हैं) का संतुलन बना रहना जरूरी है। साथ ही मिट्टी में सक्रिय केंचुओं, मित्र कीटों व जीवाणुओं की प्रक्रियाएं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, उसे भुरभुरा व अधिक जल संग्रहण क्षमता वाला बनाती है, उसमें हवा का सहज आवागमन करवाती हैं, उनकी सक्रियता जरूरी है। मिट्टी में फसलों की जड़ें गहराई तक पंहुच सके, यह भी महत्वपूर्ण है। इन सब दृष्टियों से सेन्द्रिय या प्राकृतिक खाद जो गोबर, सड़ी–गली पत्तियों आदि से मिलती है, वही सर्वोत्तम है।

अतः रासायनिक खाद पर निर्भरता समाप्त कर प्राकृतिक खाद की ओर आना उचित है। यदि जल संरक्षण होगा तो हरियाली बचेगी, तभी अधिक पशु रखे जा सकेंगे, तभी प्राकृतिक खाद प्राप्त हो सकेगी। सब कदम आपस में जुड़े हुए हैं। बैल रखने की क्षमता बढ़ेगी तो ट्रैक्टरों पर निर्भरता कम होगी। ट्रैक्टर व हारवैस्टर जैसी मशीनों का अधिक उपयोग न तो उपजाऊपन की दृष्टि से अच्छा है, न रोजगार की दृष्टि से, न खर्च व बाहरी निर्भरता बढ़ाने की दृष्टि से। जहां किसान बहुत छोटे हैं व उसकी क्षमता कम हो, वहां कई किसान मिलकर बैल रख सकते हैं।

काफी हद तक इन सब सार्थक प्रयासों की बुनियाद इस बात में है कि गांववासियों में व विशेषकर गरीब परिवारों में कितना आपसी सहयोग हो सकता है। जितना आपसी सहयोग बढ़ेगा उतना ही मंहगी मशीनों व खतरनाक रसायनों के बिना उत्पादकता बढ़ाना व वह भी टिकाऊ तौर–तरीकों से संभव बनता जायेगा।

रासायनिक खरपतवारनाशकों का उपयोग रोजगार, भूमि के उपजाऊपन, अधिक खर्चे सभी दृष्टियों से नुकसानदायक है। कुछ पौधे जिन्हें आज खरपतवार कहा जा रहा है, खाद्य गुणों से पूर्ण या अन्य दृष्टि से उपयोगी हैं। अतः जहरीले रसायन छिड़कने के स्थान पर हाथ से उन्हीं पौधों को उखाड़ना उचित है जो वास्तव में हानिकारक हैं।

रासायनिक कीटनाशकों के प्राकृतिक विकल्प के स्थान पर नीम व अनेक अन्य स्थानीय वनस्पतियां उपलब्ध हैं। स्थानीय उपलब्धि व उपयोगिता के आधार पर अलग–अलग स्थानों पर अलग–अलग वनस्पतियों का उपयोग हो सकता है। कुछ कीड़े जो बहुत नुकसानदायक माने जाते हैं, वे वास्तव में उतने हानिकारक नहीं हैं। उनके कुछ लाभकारी पक्ष भी हैं। प्रकृति के तौर–तरीके समझे बिना उससे छेड़छाड़ करने पर हम प्रकृति में मौजूद अपने अनेक मित्रों को ही नष्ट कर देते हैं। इस भूल से बचना चाहिए।

कुछ पौधे जिन्हें आज खरपतवार कहा जा रहा है, खाद्य गुणों से पूर्ण या अन्य दृष्टि से उपयोगी हैं। अतः जहरीले रसायन छिड़कने के स्थान पर हाथ से उन्हीं पौधों को उखाड़ना उचित है जो वास्तव में हानिकारक हैं।

वैज्ञानिकों की एक मुख्य भूमिका तो यही होनी चाहिए कि प्रकृति के तौर–तरीकों की सही समझ प्राप्त हो व किसान तक पहुंचे व वह बिना किसी खर्च के, इस बेहतर समझ के आधार पर अपनी व अन्य लोगों की भूख दूर करने के लिए खाद्य उगा सकें। किन्तु मौजूद व्यवस्था में वैज्ञानिकों को मशीनें, खतरनाक रसायन व उनसे जुड़े बीजों आदि बेचने वाली कंपनियों का एजेंट बनाने का प्रयास किया व इस कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। वैज्ञानिक सही अर्थों में किसानों व पर्यावरण के मित्र बनकर उन्हें प्रकृति से सहअस्तित्व के अनुकूल खेती करने में सहायता दें व स्वयं भी किसानों के गहरे और व्यापक अनुभव से सीखने को तैयार रहें तो इसे वैज्ञानिकों की सही भूमिका माना जाएगा। उन्हें छोटे किसानों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देना होगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य व कृषि संगठन ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि प्रति एकड़ कम खर्च में उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता छोटे किसानों में अधिक है। इस संगठन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक अध्ययन किया जिसका निष्कर्ष यह था कि भूमि वितरण की विषमता को दूर करने से ही विभिन्न देशों में खाद्य उत्पादन को 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। थाईलैंड के एक अन्य अध्ययन में 2 से 4 एकड़ के किसानों की तुलना 140 एकड़ से अधिक के भू–स्वामियों से की गई तो देखा गया कि छोटे किसानों की प्रति एकड़ उत्पादकता 60 प्रतिशत अधिक है।

लैटिन अमेरिका के छः देशों में (जहां भूमि वितरण की विषमताएं शायद विकासशील देशों में सबसे अधिक है) देखा गया कि छोटे किसानों की प्रति एकड़ उत्पादकता कई गुणा अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि उत्पादकता के आंकड़ों के 14 वर्षीय अध्ययन से फ्रांसिस मूर लैपे और जोसफ कालिन्स ने निष्कर्ष निकाला कि इनमें से 12 वर्षों में छोटे फार्मों की प्रति एकड़ उत्पादकता अधिक थी। अतः हमारे देश को छोटे किसानों पर आधारित खेती ही चाहिए। ❑❑

पलायन और बेरोजगारी का दंश झेलता उत्तराखण्ड

पहाड़ दूर से बहुत सुंदर लगते हैं। करीब जाइए तो उनकी हकीकत समझ में आती है। अपनी आंखों के सैलानीपन से बाहर आकर आप देखेंगे तो पाएंगे कि पहाड़ की जिंदगी कितने तरह के इम्तिहान लेती है। यह बदकिस्मती नहीं, विकास की बदनीयती है कि इन दिनों पहाड़ के संकट और बढ़ गए हैं। पहाड़ आज की तारीख में बेदखली, विस्थापन और सन्नाटे का नाम है। सदियों से पहाड़ की यही कहानी और यही सच्चाई भी है। यदि इसी प्रकार पलायन बढ़ता गया तो गांवों में इंसान नहीं जानवर देखने को मिलेंगे। पलायन को लेकर जो भी परिभाषाएं गढ़ी जाती हों, लेकिन हकीकत में इसी कठिन जीवन से मुक्ति का नाम है पलायन।

एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना में कहा गया था कि 2001 में पहाड़ी इलाकों में 53 प्रतिशत लोग थे। लेकिन 2011 में इन पहाड़ी इलाकों मात्र 48 प्रतिशत ही लोग रह गए। एनएसएसओ का 70वां सर्वे बताता है कि उत्तराखण्ड में कृषि उपज की कीमत राष्ट्रीय औसत से 3.4 गुना कम है। उत्तराखण्ड में औसत कृषि उपज कीमत 10,752 रुपए प्रति परिवार थी। जबकि कृषि उपज कीमत का राष्ट्रीय औसत 36,696 रुपए। अगर पड़ोसी राज्य हिमाचल की बात की जाए तो खेतिहर परिवार की आय हिमाचल से लगभग आधी है। उत्तराखण्ड में एक खेतिहर परिवार की औसत मासिक आय 4,701 रुपए थी। जबकि हिमाचल में खेतिहर परिवार की औसत मासिक आय 8,777 रुपए थी। कृषि प्रधान देश होने के नाते कई सीखें विरासत में हमें मिलीं, पर हम उनका सही से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे खेत छोटे हैं, बिखरे पड़े हैं और जहां गांवों में पलायन हो चुका है वहां खेत बंजर और खाली पड़े हैं। सरकार चाहे तो एक सुदृढ़ योजना बनाकर उस बंजर या खाली पड़ी कृषि

वर्ष 2011 की जनगणना में कहा गया था कि 2001 में पहाड़ी इलाकों में 53 प्रतिशत लोग थे। लेकिन 2011 में इन पहाड़ी इलाकों मात्र 48 प्रतिशत ही लोग रह गए।

– **आशीष रावत**

योग्य भूमि पर वैज्ञानिक तरीकों से कृषि करवा सकती है। यह कई स्तर पर रोजगार बढ़ाने का प्रयास हो सकता है। पाली हाउस तकनीकों से ज्यादा से ज्यादा सब्जियां उगाने पर ध्यान दिया जा सकता है। हिमाचल हमारे लिए एक उदाहरण है कि कैसे वहां कृषि को फलों की तरफ मोड़कर समृद्धि हासिल की गई।

उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के बाद बनी किसी भी सरकार ने इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए ईमानदार पहल नहीं की। अपितु मैदानी इलाकों को तेजी से विकसित करने की सरकारी नीति से असंतुलित विकास की स्थिति पैदा हो गई।

पहाड़ के गांवों से होने वाले पलायन का एक पहलू और है। वह है कम सुगम गांवों और कस्बों से बड़े शहरों अथवा पहाड़ों की तलहटी पर बसे हल्द्वानी, कोटद्वार, देहरादून, रुद्रपुर और हरिद्वार जैसे शहरों का होता बेतहाशा पलायन। मैदानी इलाकों में रहकर रोजगार करने वाले लोग सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने गांवों में दुबारा वापस जाने से ज्यादा किसी शहर में ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं। स्थिति जितनी गंभीर बाहर से दिखती है असल में उससे कहीं अधिक चिंताजनक है। इन बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्रियों के उत्पाद के साथ कुछ मात्रा में हाईस्कूल फेल–पास ग्रामीणों की जमात भी अभी तक महानगरों की ओर भाग रही है।

यह स्वीकार करना होगा कि अलग उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद पलायन की रफ्तार और संख्या में थोडा बहुत कमी जरूर दर्ज हुई, लेकिन इस कमी को उच्च शिक्षित जमात ने पूरा कर दिया है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं राजनीतिक दल लाखों की नौकरियों की बात करते हैं।

उत्तराखण्ड में सरकार कोई भी रही हो हर सरकार में बेरोजगारों के नाम पर सिर्फ छल हुआ। चुनाव के समय हर दल ने वायदे किए, लेकिन जब वायदों को पूरा करने की बारी आई, तो किनारा कर गए।

जब 9 नवंबर, 2000 को उत्तराखण्ड राज्य का गठन हुआ तो उस वर्ष केवल दो महीने के भीतर उत्तराखण्ड में 2,70,114 बेरोजगार रजिस्टर्ड हुए थे। बदले में 37 युवाओं को रोजगार मिल पाया था। उसके अगले वर्ष 3,13,185 बेरोजगारों की तुलना में 836 को रोजगार मिला था। बात रोजगार की हो रही है तो वर्ष 2005 रोजगार के हिसाब से बेरोजागरों के लिए सबसे धनी वर्ष रहा। इस वर्ष 3,80,217 रजिस्टर्ड बेरोजगारों की तुलना में 6,094 बेरोजगारों को रोजगार मिला। वर्ष 2007 में 3,856 युवाओं को रोजगार मिला। वर्ष 2006 में 3,169 और वर्ष 2002 में 2,930 बेरोजगारों के रोजगार के सपने पूरे हुए। सच्चाई यह भी है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर ईमानदार कोशिश हुई ही नहीं। हुक्मरान तो सिर्फ 'सत्ता' के खेल में उलझे रहे। जिन पर राज्य के भविष्य की जिम्मेदारी रही वे सिर्फ अपनी तरक्की के फेर में व्यस्त रहे।

बेरोजगार युवाओं की तस्वीर इस बात की बानगी है कि आज पढ़ाई–लिखाई कामयाबी की गारंटी कतई नहीं है। सेवायोजन विभाग में पंजीकृत बेरोजगारों के आंकड़ों की बात करें तो दून में सबसे अधिक 1,72,136 बेरोजगार हैं। ये बेरोजगार 4–5 वर्षों से रोजगार की आस लगाए बैठे हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये शिक्षित नहीं हैं। इनकी शैक्षिक योग्यता पर नजर डालें तो 48 फीसद बेरोजगार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। देहरादून जनपद में कुल बेरोजगारों में 10वीं पास महज 26,380 हैं, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार की संख्या 28,993 है।

उत्तराखण्ड में सरकार कोई भी रही हो हर सरकार में बेरोजगारों के नाम पर सिर्फ छल हुआ। चुनाव के समय हर दल ने वायदे किए, लेकिन जब वायदों को पूरा करने की बारी आई, तो किनारा कर गए। साफ है कि राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जिन्हें छोटी–छोटी नौकरियों की तलाश है। हालात बेहद चिंताजनक हैं। आज बेरोजगारी चरम पर है। पढ़े–लिखे युवा बेरोजगार भटक रहे हैं। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। लोग नियमित आमदनी में घर नहीं चला पा रहे हैं।

सच्चाई यह है कि पहले आपदा, फिर नोटबंदी और अब जीएसटी लागू होने के बाद बेरोजगारी का आंकड़ा और तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी किसी गंभीर चुनौती से कम नहीं, यह सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है। यदि देवभूमि में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो इसके दूरगामी परिणाम राज्य के भविष्य के लिए घातक भी हो सकते हैं। ❑❑

(लेखक भारत नीति प्रतिष्ठान से संबंधित हैं)

वैदिक जीवन पद्धति से अनुप्राणित हो शिक्षा

प्राचीन शिक्षण में वैदिक जीवन पद्धति से अनुप्राणित भारतीय सभ्यता व संस्कृति पूर्ण रूप से विकसित थी तथा भारत पूरे विश्व में अत्यंत समृद्ध एवं वैभवशाली राष्ट्र था। प्राचीन भारत में वैदिक काल में ऋषि मुनियों के तप और साधना द्वारा प्रतिपादित गुरूकुल पद्धति से शिक्षा प्रदान की जाती थी। विद्यार्थी जीवन के प्रथम 25 वर्ष, ब्रह्मचार्य आश्रम में गुरू की सेवा करते हुए संस्कार व शिक्षा दोनों प्राप्त करते थे। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय में कहा गया है–

''विद्यास्ति ज्ञान विज्ञान दर्शनः संस्क्रियात्मनि''।। ब्रह्मसूत्र, अ.1।।

अर्थात्– ज्ञान विज्ञान एवं दर्शन की शिक्षा द्वारा आत्मा में संस्कार उत्पन्न करना ही विद्या है।

हिन्दु शास्त्रों में सेवा, आदर–सम्मान जैसे संस्कारों को जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसका उल्लेख मनु स्मृति में इस प्रकार मिलता है–

''अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो पसेविनः।
चत्वारि तस्यवर्धनों आयुर्विद्या यशोबलम्।।'' (मनु स्मृति,2/121)।

अर्थात– आदर सम्मान करने तथा नित्य वृद्धों की सेवा करने जैसे संस्कार से मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल चारों में वृद्धि होती है।

वैदिक शिक्षा पद्धति में यज्ञ हवन, ध्यान योग द्वारा विद्यार्थी में सात्विक मनोवृत्ति निर्मित की जाती थी। यम नियम के पालन द्वारा राग, द्वेष, मद, मोह, लोभ जैसे विकारों से मुक्त कर आत्मिक शुद्धि करने पर आंतरिक शक्तियों को विकसित किया जाता था। इस प्रकार निर्दोष व निरोगी संस्कारित विद्यार्थी के तेजोमय व्यक्तित्व का निर्माण होता था। विद्यार्थी वेद–वेदांत का अध्ययन करते हुए चिंतन–मनन की प्रक्रिया द्वारा जीवन के सत्यों को उजागर करते थे। शिक्षा पूर्ण होने पर विद्यार्थी आत्म कल्याण के साथ–साथ जन कल्याण के मार्ग

वैदिक शिक्षा पद्धति में यज्ञ हवन, ध्यान योग द्वारा विद्यार्थी में सात्विक मनोवत्ति निर्मित की जाती थी। यम नियम के पालन द्वारा राग, द्वेष, मद, मोह, लोभ जैसे विकारों से मुक्त कर आत्मिक शुद्धि करने पर आंतरिक शक्तियों को विकसित किया जाता था।

– **डॉ. रेखा भट्ट**

पर अग्रसर होते थे। शिक्षा के समावर्तन के अवसर पर गुरू द्वारा धर्म का पालन करने अर्थात कर्त्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती थी, क्योंकि धर्म को ही चारों पुरूषार्थों– धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में शेष तीनों का नियामक माना गया है।

वेदों–उपनिषदों के आध्यात्मिक ज्ञान को सर्वमान्य महाग्रंथ गीता ने, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के रूप में ढालकर जन सामान्य में सामाजिक चेतना जागृत की। महाभारत काल के लगभग डेढ़ सहस्त्र वर्ष बाद भारत में अंधकार युग प्रारंभ हुआ। भारत के सम्राट अशोक द्वारा कलिंग युद्ध में बौद्ध धर्म अपनाते हुए क्षत्रिय धर्म से वैराग्य ले लेने के कारण भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा में शिथिलता आ गई।

12वीं शताब्दी से अरबी, फारसी आक्रमणों के साथ बाहरी सभ्यता के आगमन से वैदिक जीवन पद्धति में धार्मिक शिक्षण व आचरण का प्रभाव बढ़ने लगा। अनेक सभ्यताओं व संस्कृतियों के खान–पान, रहन–सहन, आचार–विचार, का भारतीय जीवन पद्धति में योग बढ़ता रहा किन्तु ऐसी अनेक धार्मिक पद्धतियां भी जुड गई जैसे तंत्र–मंत्र, प्रेत पूजा, बलि प्रथा आदि जो हिन्दु शास्त्रों व सदाचारों के विरूद्ध होते हुए भी लोगों के आजीविका एवं लाभ पाने का माध्यम बन गई। भारतीय आध्यात्मिक जीवन पद्धति में धार्मिक विकृतियों के कारण हिन्दु संस्कृति अंधविश्वास–आडंबर युक्त तथा रूढ़िवादी परंपराओं के रूप में प्रचारित होने लगी। अनेक धार्मिक प्रचलनों में भारतीय जीवन पद्धति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये जैन, बौद्ध, सिख आदि अनेक पंथो का अभ्युदय हुआ और इस्लाम सहित सभी पंथ व संस्कृतियां भारत की विशाल सनातन संस्कृति के समुद्र में समाहित होते चले गए। समाज में कार्य विभाजन एवं कार्य–कौशल को

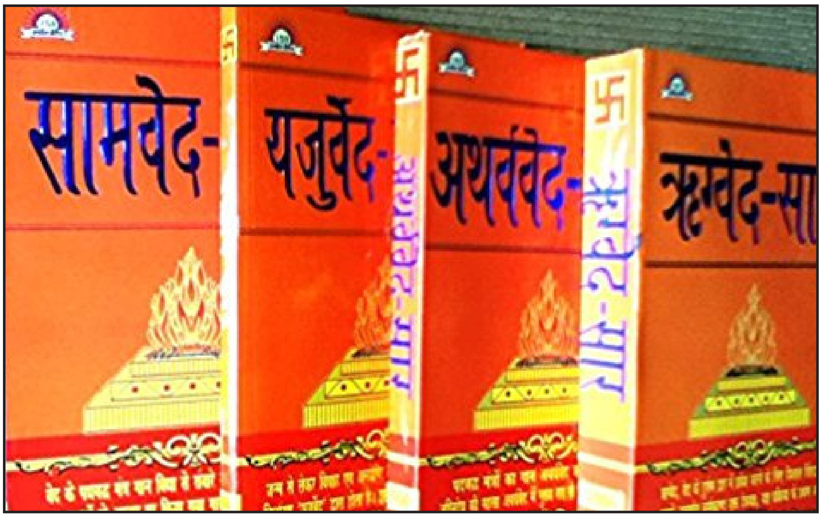

18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय जीवन पद्धति को समूल नष्ट करने के लिये गुरूकुल बंद करवा दिये और भारतीयों को षडयंत्रपूर्वक अंग्रेजी शिक्षण द्वारा जीवन मूल्यों से रिक्त भौतिकतावादी और उपभोक्तावादी जीवन पद्धति की ओर प्रवृत्त कर दिया।

पारिवारिक व्यवसाय के रूप में उन्नत करने तथा सामाजिक समरसता बनाये रखने पर आधारित भारतीय जीवन पद्धति की वर्ण व्यवस्था मध्यकाल तक धीरे–धीरे जाति प्रथा में बदल गई।

मुगल साम्राज्य के निरंतर विस्तार एवं स्थायित्व का शिक्षा के साथ समाज के सांस्कृतिक मूल्यों पर भी गहरा प्रभाव पडा। कबीर, नानक, रहीम आदि संतों के प्रभाव से अनेक पंथों का विकास हुआ और उनका भारतीय संस्कृति में समावेश हुआ। विभिन्न धार्मिक मतों द्वारा प्रचलित जीवन पद्धति में प्रवृत्ति और निवृत्ति के मार्गों के बीच भटकते समाज को महर्षि दयानन्द सरस्वती के पुनः "**वेदों की ओर लौटों**" वाक्य ने सभी संस्कृतियों के समन्वित मार्ग की दिशा प्रदान की।

18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय जीवन पद्धति को समूल नष्ट करने के लिये गुरूकुल बंद करवा दिये और भारतीयों को षडयंत्रपूर्वक अंग्रेजी शिक्षण द्वारा जीवन मूल्यों से रिक्त भौतिकतावादी और उपभोक्तावादी जीवन पद्धति की ओर प्रवृत्त कर दिया।

20वीं सदी के मध्य में भारत जब ब्रिटिश औपनिवेशिकता से मुक्त हुआ तब तक पाश्चात्य देशों में औद्योगिक क्रांति से हुए आर्थिक विकास की तुलना में भारत पिछड़ गया था। भारत में 150 वर्षों से प्रचलित ब्रिटिशकालीन मैकॉले शिक्षण पद्धति के कारण क्षतिग्रस्त वैदिक ज्ञान–विज्ञान व प्रौद्योगिकी को उन्नत करना संभव नही था। स्वतंत्र भारत में भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षण पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करना था, परंतु तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों और ब्रिटिश प्रभाव से युक्त राजनैतिक नेतृत्व के कारण संभव नही हो सका। स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी भारत में मैकॉले शिक्षण पद्धति के अनुकरण से युवा पीढ़ी जीविका प्राप्त करने के योग्य तो बनती है किंतु व्यक्तित्व निर्माण द्वारा समाज

व राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं कर पाती। ऐसी संस्कारविहीन शिक्षण पद्धति के दूरगामी प्रभाव आज समाज के सभी क्षेत्रों में दिखाई पडते है। तथा कथित शिक्षित किंतु भारत के इतिहास से अनभिज्ञ कलाविद् भारत की वीरांगनाओं की गौरवगाथा को मनोरंजन का माध्यम बनाकर आने वाली पीढ़ियों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। पाश्चात्य जीवन पद्धति का अंधानुकरण कर रही आधुनिक पीढ़ी को भारत के साहित्य व इतिहास का तथ्यों सहित ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए तभी वे भारतीय सभ्यता व संस्कृति पर गर्व करेंगे।

भारतीय संस्कृति अनेक सभ्यताओं और संस्कृतियों का समन्वय करते हुए आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है, क्योंकि वैदिक शिक्षण से संबद्ध जीवन पद्धति में व्यवस्थित ज्ञान की जड़ें हजारों वर्षों पूर्व समाज की गहराई तक व्याप्त थी। वैदिक शिक्षण पद्धति में आत्म–साक्षात्कार द्वारा सत्य की खोज और प्रकृति के रहस्यों को भेदने की अपार क्षमती थी। यही विशुद्ध ज्ञान, वैदिक ऋचाओं में जीवन के सत्य के रूप में उद्धत किया गया था, जो आज भी संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिकों द्वारा खोज व अनुसंधान का वैज्ञानिक आधार बना हुआ है। विश्व के प्राचीनतम वेद–ऋग्वेद में आज के कॉपरनिकस के सिद्धांत का वर्णन कर दिया गया था, जिसके अनुसार पृथ्वी

भारतवर्ष में कालातीत वैदिक कालीन जीवन पद्धति ही भारतीय संस्कृति की पोषक रही है। इससे वैदिक अध्ययन व आध्यात्मिक चिंतन मनन की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी की सोच को नई दिशा मिलेगी।

सूर्य के चारों और परिक्रमा करती है। जर्मनी द्वारा खोजे गये जल में भी जीवन हैं मंत्र का मूल वेदों ने नदियों को दैविक स्वरूप प्रदान कर जलपूजन के रूप में व्यक्त किया था। संपूर्ण सृष्टि के कल्याण को वेदों में जीवनदायी वृक्षों तथा जीवों के पूजन की परंपरा के रूप में स्थापित किया गया था जो आज जैविक संपदा के संरक्षण के रूप में ज्ञात किया गया है। भारतीय नववर्ष की प्राचीन परंपरा तात्कालिक ब्रह्माण्डीय अंवेषण के उन्नत खगोलशास्त्र की पुष्टि करती है। परंतु यह आश्चर्यजनक है कि वर्तमान शिक्षा में भारतीय गौरवशाली अतीत के ज्ञान विज्ञान संबंधी पाठ्यक्रम नहीं है तथा वर्तमान भारतीय पीढ़ी इससे अनभिज्ञ भी है।

भारतीय परंपराओं की वैज्ञानिकता और शाश्वत मूल्यों पर आधारित वैदिक जीवन पद्धति के कारण ही भारत में भिन्न–भिन्न संस्कृतियां एकसूत्र में बंधी हुई है। धार्मिक संकीर्णता और हठधर्मिता से परे आज भी वैदिक संस्कृति ही प्रत्येक भारतवासी को अनुप्राणित करती है। संपूर्ण जगत को बंधुत्व भाव से जोड़ लेने वाली सनातन वैदिक संस्कृति ही हिन्दुत्व का पर्याय बन गई है।

रवीन्द्र नाथ ठाकुर के शांति निकेतन, गांधी आश्रम, पांडुचेरी के अरविंद आश्रम और इवान इलिच के स्कूल रहित शिक्षण में शिक्षा के साथ संस्कार प्रदान करने के प्रयास किये गये। इन्हें आगे बढ़ाते हुए आधुनिक शिक्षण में पुनः भारतीय संस्कृति को जीवंत करने की आवश्यकता है। वैदिक शिक्षण पद्धति पाठ्यचर्या का ही नही, विद्यार्थी की दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा बन सके। उन्हें वेद वेदांगों में समाये अतुलित ज्ञान की संपदा को जानने का अवसर मिले। मातृभाषा में शिक्षण द्वारा ही विद्यार्थी अपनी पुरातन जीवन पद्धति को आत्मसात करता है। भारतीय ग्रंथों के शिक्षण द्वारा विद्यार्थी मनुष्य के जीवन में कर्म और पुरूषार्थ का महत्व पहचानेंगे तभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। संस्कारित युवाओं के आध्यात्मिक लक्ष्य का निर्धारण होगा तथा उनमें आत्म विश्वास व स्वविवेक जागृत होगा।

भारतवर्ष में कालातीत वैदिक कालीन जीवन पद्धति ही भारतीय संस्कृति की पोषक रही है। इससे वैदिक अध्ययन व आध्यात्मिक चिंतन मनन की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी की सोच को नई दिशा मिलेगी। प्राचीन विज्ञान प्रौद्योगिकी में खोज व अंवेषण के द्वारा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होगा तथा वैदिक जीवन पद्धति द्वारा संस्कार व राष्ट्रीयता का भाव देने में सक्षम शिक्षा ही सार्थक होगी। ❑❑

संविधान से ही होता है स्वतंत्रता का अहसास

गणतंत्र दिवस पर स्वतंत्र भारत ने अपने प्रशासन व शासन को चलाने के लिये अपने द्वारा बनाये गये नियमों की पुस्तक, जिसको हम संविधान कहते है, स्वीकार किया था, जिसमें हमने प्रण लिया था कि हम देश को धर्मनिरपेक्ष, गुटनिरपेक्ष के रास्ते पर चलाते हुए देश का विकास करेंगे। जिसमें लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी होगी, देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आजादी होगी, सभी देशवासी को कहीं भी अपने व्यवसाय को चलाने की आजादी होगी, किसी को कहीं भी बसने की आजादी होगी, इत्यादि आजादियां हमको इस पुस्तक संविधान से मिली है। इस संविधान को उस समय के तपे तपाये मुर्धन्य व बुद्धिजीवी लोगों ने लगभग दो वर्ष के आपसी विचार विमर्श करके बनाया था तथा संविधान के रचयिता डॉ. भीमराव अंबेडकर माने गये।

बाद में संविधान में देश के लोगों के द्वारा चुने हुए लोकसभा व राज्यसभा के दो तिहाई सदस्यों के आपसी मतों से संविधान में अब तक 103 के लगभग संशोधन भी हुए, जिससे हम इस संविधान को एकदम से सख्त भी नहीं कह सकते है। लोगों की राय कभी भी जानकर ही संविधान में समय–समय पर संशोधान होते रहे है, जिससे आज भारत का संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान समझा जाता है। इस संविधान ने देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बदलाव भी किये हैं।

राजनीतिक तौर पर देश के सभी राजाओं, महाराजाओं, नबाबों, सम्राटों व शंहशाहों के पदों को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना की गई, जिससे मतदान करके देश की जनता अपने सत्ताधीशों का चुनाव करते है।

– डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

राजनीतिक तौर पर देश के सभी राजाओं, महाराजाओं, नबाबों, सम्राटों व शंहशाहों के पदों को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना की गई, जिससे मतदान करके देश की जनता अपने सत्ताधीशों का चुनाव करते है। गांव व शहर के पंच व सभासदों से लेकर राष्ट्रपति तक को लोग चुनते है, जिसके पक्ष में अधिक लोग होते है, उसी को चुन लिया जाता है। उसका कार्यकाल निर्धारित होता है तथा अपने कार्यकाल में वह देश, राज्य, नगरपालिका अथवा गांव की पंचायत की जनता के कल्याण के लिये कार्य करता है। संविधान लागू होने से सामाजिक परिर्वतन देखने को मिला है। संविधान में दिये गये अधिकारों के आधार पर दलित, दबे व कुचले, आदिवासी इत्यादि लोगों को मान–सम्मान देते हुए उनके आर्थिक उत्थान के लिए आरक्षण लागू किया गया। बाद में इसमें पिछडे व अति पिछडे लोगों को भी शामिल किया गया।

देश की स्वतंत्रता के इन 70 वर्षों में समाज में एक क्रांति होती देखी जा रही है, जिसमें लोगों के दिलों में दूसरे संप्रदायों, जाति व भाषा के लोगों से स्नेह का परिमार्जन हुआ है तथा लोगों में आपसी दूरियों को कम किया गया है। आर्थिक क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन देखें गये हैं। देश में किसी भी प्रकार क्षेत्रीयता, भाषा, वर्ण व जाति इत्यादि को प्रमुखता न देते हुए आर्थिक उत्थान के लिये बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है जिससे बड़े–बड़े लोहे के कारखाने स्थापित किये गये, कृषि प्रधान देश के खेतों तक सिंचाई के लिए नदियों पर बड़े–बड़े बांध स्थापित किये गये, सिंचाई की अन्य व्यवस्था की गई, सडकों का निर्माण राष्ट्रीय व राज्यीय आधार पर हुआ, जिससे सड़कों का जाल बिछाया गया, रेल लाइनों का

निर्माण हुआ, बिजली का उत्पादन बढ़ा, बैंकों का जाल बिछाया गया, प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई। इसे संविधान की बदौलत ही देश में तकनीकी क्रांति, सूचना क्रांति के रूप में सबके सामने हुई है। संविधान के दायरे में रहकर लोकसभा, राज्यसभा व देश की विभिन्न विधानसभाओं व विधान परिषदों में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं।

हम सभी भारतीयों को अपने देश के संविधान पर गर्व होना चाहिए। हमें उन बातों से दूरी बनानी चाहिए जिनसे भारत की विश्व स्तर या किसी भी स्तर पर अवमानना होती हो, हमें अपने मन भेदों को भारत में ही मंचों पर उठाना चाहिए। अभी 12 जनवरी 2018 को ही भारत के उच्चतम न्यायालय के चार माननीय न्यायमूर्तियों के द्वारा जिस प्रकार प्रेस कार्फ्रेंस करके भारत की उच्चतम संस्था के बारे में नुक्ताचीनी की गई, वह किसी भी दृष्टि से भी आम से आम भारतीय की नजरों में भी उचित नहीं कहा जा सकता। उनको अपने मन भेद सभी न्यायमूर्तियों की सभा बुलाकर दूर करनी चाहिए थी, किसी भी कीमत पर इस उच्चतम संस्था के प्रति देश के लोगों का अविश्वास उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए था।

भारतीय संविधान ऐसी नीति सामने रखता है जो नागरिकों पर केंद्रित है और जहां राज्य व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। समुदाय या समूह आधारित पात्रताओं की व्यवस्था है लेकिन अस्थायी तौर पर, ताकि समय बीतने के साथ व्यक्तिगत अधिकारों को फलने–फूलने का अवसर मिले।

परंतु संविधान की इस मूल भावना को ध्यान में न रखकर समुदाय या समूह आधारित अराजक और संकीर्ण पात्रताओं का दौर देखने को मिल रहा है। अगर यह स्थायी विशेषता बन गया तो व्यक्तिगत अधिकारों की सर्वोच्चता का क्या होगा? जोकि संविधान की प्रमुख खासियत बना हुआ है। समुदाय अधारित पात्रताओं के बल पर हम राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं कर सकते है। संविधान तैयार करने वालों ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जहां हर नागरिक अपनी पूरी क्षमता विकसित कर सके और जाति, धर्म आदि से परे श्रेष्ठता हासिल कर सके। यह एक ऐसा समाज होगा जहां अवसरों की समानता होगी, न कि पात्रताओं की और अवसर की, यह समानता तभी तैयार हो सकती है जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सबके लिये हो और भेदभाव नहीं हो। अगर देश इस लक्ष्य की ओर आगे बढता है तभी हम लोगों की रचनात्मक ऊर्जा का फायदा उठा पायेंगें और व्यापक गरीबी, बीमारियों और सामाजिक व आर्थिक असमानता को दूर कर पायेंगे। संविधान बहुत आधारभूत ढ़ंग से यह मानता रहा है कि देश की जनता ही सबसे कीमती संसाधन है और एक लोकतंत्र के फलने–फूलने, उसके भविष्य के निर्धारण में मानव संसाधान की अहम भूमिका है।

प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक मात्र कुछ संस्थाओं को छोडकर शेष संस्थाएं चिंताजनक स्थिति में है। शिक्षकों का व्यवहार विद्यार्थियों के प्रति अत्यंत ही कटु हो रहा है। विद्यार्थी भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे है।

उच्च शिक्षा के प्रति देश में जिस प्रकार का माहौल बनता जा रहा है उसको उचित नहीं कहा जा सकता है। उच्च शिक्षा व अन्य शिक्षा को कमाई का एक साधन मानते हुए इसको एक उद्योग के रूप में पल्लवित किया जा रहा है। जिसमें शिक्षा कम, शोषण अधिक है। छात्र, छात्राओं, अभिवावकों, शिक्षकों व शिक्षा में लगे कर्मचारियों का व्यापक पैमाने पर शोषण किया जा रहा है। एक भैंसा बुग्गी चलाने वाला हवाई जहाज उडाने के लिए पायलट बन गया है, जो न तो हवाई जहाज उडा पा रहा है और सरकार ने जिस पायलट को हवाई जहाज उडाने के लिए कहा वह बुग्गी को सही ढ़ंग से चला नहीं पा रहा है, जिससे न तो हवाई जहाज उड पा रहा है और न ही बुग्गी चल पा रही है। इससे देश की गाडी बे–पटरी हो कर रह गई है। देश को चलाने के लिए आज वैश्विक प्रतियोगिता से होकर गुजरना पड रहा है। परंतु हमारी कुल बुद्धि का 100 प्रतिशत नहीं, मात्र 50 प्रतिशत से भी कम बुद्धि का ही उपयोग हो रहा है। इसी कारण देश में शिक्षा का वातावरण निरंतर गिर रहा है और देश की प्रतिभाएं विदेश को पालायन कर वहां की प्रगति व उन्नति कर रही हैं। देश का 45,000 करोड रूपया प्रतिवर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में हमारे देशवासियों के बच्चे फीस के नाम पर वहां दे रहे है। प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक मात्र कुछ संस्थाओं को छोडकर शेष संस्थाएं चिंताजनक स्थिति में है। शिक्षकों का व्यवहार विद्यार्थियों के प्रति अत्यंत ही कटु हो रहा है। विद्यार्थी भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे है। हम सब गणतंत्र की इस बेला में शिक्षा पर इसलिये विचार कर रहे है कि हम सभी उच्च शिक्षा से जुड़े हुए है।

देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी व कर्तव्यों को समझते हुए, इसके उत्थान के लिए सतत् प्रयत्नशील रहना चाहिए व संविधान से ही हमें अपनी स्वतंत्रता का मखमली अहसास होता है।

डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल, प्राचार्य, ताराचंद वैदिक पुत्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर 251001 (उ.प्र.)

डॉक्टरी पेशे की प्रतिष्ठा पर संकट

पहले मैक्स, फिर फोर्टिस और फिर मेदांता। आरोप लगा कि मौतें इलाज में लापरवाही के कारण हुई। डेंगू पीड़ित बच्चे के पिता को पहले तो 16 लाख रुपये का खर्च बता दिया। पिता ने अपना घर गिरवी रखकर किसी तरह 15.88 लाख रुपये का इंतजाम किया। अस्पताल को पैसे मिल गये, तो पीड़ित को सरकारी अस्पताल का रास्ता दिखा दिया। जहां जाकर बच्चे की मौत हो गई। क्रूरता की हद यह कि सरकारी अस्पताल में ले जाने के लिए निजी–अस्पताल ने अपनी एंबुलेंस तक मुहैया नहीं कराई। ऐसा नहीं है कि इलाज में लापरवाही की ये पहली, दूसरी अथवा तीसरी घटनायें थीं। सरकारी अस्पतालों में इनसे भी ज्यादा लापरवाही बरतने के मामले संभव हैं। किंतु इलाज को लेकर निजी अस्पतालों में हुए अपराध ज्यादा संगीन इसलिए मानने चाहिए, चूंकि मरीज की दुर्दशा के ज्यादातर मामलों में वजह लापरवाही से ज्यादा, पूर्ण नियोजित लालच होता है। पैर की हड्डी में आई मामूली टूट, जो प्लास्टर से ठीक हो सकती है, उसका अनावश्यक ऑपरेशन करके सवा लाख रुपये तक वसूल लेना। दिल के जिन मरीजों को स्टंट की जरूरत नहीं, उन मरीजों को भी स्टंट डाल देना। कैंसर न होने पर भी कैंसर बता देना; ताकि मरीज के सगे–संबंधी कुछ भी खर्चने को तैयार हो जायें। इसके लिए पैथोलॉजी लैब से मिलकर गलत रिपोर्ट जारी करा देना। गांव–कस्बे के डॉक्टरों द्वारा शहर के प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को भेजना। बदले में प्राइवेट अस्पताल द्वारा उन्हें कमीशन देना। इस लालच को डॉक्टरी के पेशे में आई नैतिक गिरावट मानें या निजी अस्पतालों को सरेआम डाली गई डकैती डालने की दी गई शासकीय–प्रशासकीय छूट?

राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक अति वरिष्ठ डॉक्टर ने मुझसे कहा कि उन्हें अब अपने पेशे से घिन आती है। जबकि ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों में भगवान एकदम ही गायब हो गया है।

– अरूण तिवारी

राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक अति वरिष्ठ डॉक्टर ने मुझसे कहा कि उन्हें अब अपने पेशे से घिन आती है। जबकि ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों में भगवान एकदम ही गायब हो गया है। वर्षों पहले मैंने दिल्ली के सुचेता कृपलानी अस्पताल के एक डॉक्टर को एक मरीज की जरूरत की दवाई बाहर से मंगाने के लिए चंदा इकट्ठा करते देखा। आज भी मात्र पांच रुपये फीस लेकर चमड़ी का सफल इलाज करने वाले मांड्या (कर्नाटक) के डॉक्टर एस.सी. शंकर गौड़ा का किस्सा आपने सुना ही होगा। हकीकत यह है कि गिरावट पेशे में नहीं, अपितु हमारे निजी चिकित्सा तंत्र में आई है। निजी चिकित्सा संस्थान चलाने वालों ने इलाज करने को पूरी तरह एक बाजारू कारोबार मान लिया है और चिकित्सक को बाजार बढ़ाने वाला मार्किटिंग एजेंट। निजी अस्पताल का प्रबंधन जिन डॉक्टरों को नौकरी पर रखता है, उन पर दबाव डालता है कि वे उनको दी जा रही मोटी पगार के बदले ज्यादा से ज्यादा कमाई करायें। प्रबंधन द्वारा डॉक्टरों को एक महीने में कम से कम कितने ऑपरेशन करने हैं; इसका लक्ष्य दिया जाता है। जच्चा–बच्चा की सुरक्षा के नाम पर ज्यादातर प्रसव,

ऑपरेशन से ही कराये जाते हैं। वास्तविक कारण होता है, ज्यादा कमाई का लालच। इस बाजार को बढाने में सरकारी नीतियों, पैथोलॉजी जांच प्रयोगशालाओं, दवा तथा चिकित्सा मशीन की कंपनियों ने पूरी मदद की है। दवाई कंपनियों की मदद से लगाये जाने वाले चिकित्सा कैंप अंततः बाजार बढ़ाने का ही काम करते हैं। टीका, आयोडिन नमक, बोतलबंद पानी, आर. ओ. मशीन, रिफाइंड तेल, क्रीम जैसे उत्पाद बेचने के लिए लोगों में भ्रम फैलाने का काम डॉक्टरों के जरिए ही किया जाता रहा है। सबसे ज्यादा मदद की है, बीमा कंपनियों की चिकित्सा पॉलिसियों तथा निजी अस्पतालों को सरकारी पैनल पर डालने की नीति ने।

निजी अस्पतालों में आने वाले मरीज से सबसे पहले पूछा जाता है– ''आपके पास कोई हैल्थ पॉलिसी या कार्ड है?'' हकीकत यह है कि निजी अस्पताल उन्हीं को भर्ती करने में रुचि लेते हैं, जिनके पास कोई कार्ड या पॉलिसी हो। रोग चाहे मामूली ही क्यों न हो, वे कार्ड की अधिकतम संभव आर्थिक सीमा के अनुसार इलाज का 'पैकेज' पहले ही बता देते हैं। हकीकत यह भी है कि जिनके पास जितने की चिकित्सा पॉलिसी है, वे मरीज उतने खर्च तक इलाज की कतई परवाह नहीं करते; चाहे वह नाजायज ही क्यों न हो। सरकारी कर्मचारी तो बिल्कुल नहीं करते। अलबत्ता कुछ कर्मचारी तो साल में कुछ दिनों के लिए पैनल के किसी अस्पताल में इसलिए भर्ती हो जाते हैं; ताकि सरकारी छुट्टी पर एक–आध सप्ताह फाइव स्टार सुविधा वाली जगह में आराम फरमा सकें। गरीबी रेखा से नीचे वाले आयवर्ग को वर्ष में 30 हजार रुपये तक की चिकित्सा कराने की आजादी देने के लिए 'स्मार्ट कार्ड' बनाये गये हैं। बिजनौर के एक डॉक्टर के मुताबिक, जिला व तहसील स्तर के ज्यादातर नर्सिंग होम इसी कार्ड पर जिंदा हैं। गांव से आये अनपढ़ मरीजों को नहीं पता होता कि वे जिस फार्म पर अगूंठा लगा रहे हैं, उनमें क्या लिखा है और उनके इलाज के नाम पर मनचाही राशि लिख दी जाती है। यह टैक्स के रूप में लोगों द्वारा सरकार को दी जा रही गाढ़ी कमाई की बर्बादी नहीं है तो और क्या है?

एक वक्त था, डॉक्टर नब्ज, लक्षण अथवा स्टेथोस्कोप की मदद से बीमारी का पता लगा लेते थे। निस्संदेह, पैथोलॉजी जांच ने बीमारी की स्टीक पहचान करने को आसान बनाया है। किंतु साधारण सी भी बीमारी की पहचान के लिए पूरी तरह पैथोलॉजी जांच रिपोर्ट पर निर्भर हो जाने की चिकित्सा पढ़ाई ने इलाज को बेहद मंहगा बना दिया है। यदि भारत में इलाज की मंहगाई और लूट घटानी है, तो हैल्थ पॉलिसी, कार्डों और सरकारी पैनल में निजी अस्पतालों का ईमानदार विकल्प सोचना होगा। डॉक्टरी की पढ़ाई में पैथोलॉजी जांच की बजाय, नाड़ी ज्ञान और लाक्षणिक विज्ञान पर जोर बढ़ाना होगा। ऐसा कानून बनाना होगा, जिसके तहत् मरीज को उसकी जांच रिपोर्ट, बीमारी तथा इलाज के चिकित्सकीय पहलुओं के बारे में उसकी भाषा में बताना अनिवार्य हो। दवाइयों की कीमतों तथा पैथोलॉजी जांच की फीस पर लगाम सुनिश्चित करनी ही होगी। चुनिंदा साधारण बीमारियों के लिए लोगों को मंहगे अस्पतालों तथा मंहगे डॉक्टरों के फेर में पड़ने से रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों के तंत्र को तकनीकी और विशेषज्ञता स्तर पर पूरी तरह समृद्ध तथा ईमानदार सेवा केंद्रों में तब्दील करना होगा। सरकारी जिला अस्पतालों में जांच व दवा की उपलब्धता बढ़ानी होगी। बिना डिग्रीधारी अचूक नाड़ी वैद्यों, नस व हड्डियों के अद्भुत जानकारों, सांप काटे का अचूक इलाज करने वालों तथा दाइयों को उनकी प्रमाणिक कुशलता के आधार पर मान्यता देने की प्रक्रिया शुरु करनी होगी। संभवतः राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बिल में शामिल ब्रिज कोर्स का ताजा प्रस्ताव इसके रास्ते खोले।

यदि सरकार चिकित्सा में बाजार की गिरोहबंदी को न तोड़ सकी, तो तय मानिए डकैती की वजह निजी चिकित्सा तंत्र भले ही हो, खामियाजा अंततः डॉक्टरी पेशे को ही भुगतना पड़ेगा।

यदि सरकार चिकित्सा में बाजार की गिरोहबंदी को न तोड़ सकी, तो तय मानिए डकैती की वजह निजी चिकित्सा तंत्र भले ही हो, खामियाजा अंततः डॉक्टरी पेशे को ही भुगतना पड़ेगा। अभी मरीज ने डॉक्टरों को भगवान मानना बंद किया है; आगे चलकर वह पूरी तरह डकैत मानने लगेगा। दुखद यह होगा कि तब मरीज, डॉक्टरों से उसी तरह मुकाबला करेगा, जैसे डकैती पड़ने पर डकैतों से करता है। मरीजों के तीमारदारों द्वारा डॉक्टरों से की जाने वाली बदतमीजी की बढ़ती घटनायें इसका संकेत हैं। ऐसे में डॉक्टरी पेशे के प्रति विश्वास को बचाना बेहद जरूरी है। इसके लिए निजी चिकित्सा तंत्र को बाध्य करना जरूरी है। सरकार, मरीज और डॉक्टर मिलकर ऐसा करें; ताकि डॉक्टर को मिला भगवान का दर्जा और पेशे की प्रतिष्ठा, दोनों बचे रहें। यह मरीज के हित में भी है और डॉक्टर के हित में भी। ❑❑

स्वास्थ्य योजना से दूर रखें विदेशी कंपनियों को: स्वदेशी जागरण मंच

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण के दौरान स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रस्ताव रखा था। इस योजना के जरिये उन्होंने 10 करोड़ गरीब परिवारों को मदद मिलने की उम्मीद जताई है। इसके बाद स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार से एक अपील की है। पीटीआई के मुताबिक मंच ने कहा है कि इस बीमा योजना से विदेशी कंपनियों को दूर रखा जाना चाहिए।

स्वदेशी जागरण मंच के सह–संयोजक अश्विनी महाजन का कहना है, 'केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना सराहनीय है। इससे देश की करीब 50 करोड़ की आबादी लाभान्वित होगी। लेकिन यह भी जरूरी है कि देश के मूल्यवान संसाधनों को भारतीय कंपनियों तक ही सीमित रखा जाय।'

बता दें कि बजट भाषण के दौरान प्रस्तावित इस योजना को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना भी बताया गया है। इस योजना के तहत गरीबों को पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।

'मेक इन इंडिया' के लिए घातक है एफडीआईः अन्नदा शंकर

'खुदरा व्यापार में एकल समान पर 100 प्रतिशत पूंजी निवेश (एफडीआई) का स्वदेशी जागरण मंच विरोध करता है। कारण यह है कि इससे वर्तमान सरकार द्वारा चलायी जा रहीं 'मेक इन इंडिया', 'मेड बाय इंडिया' जैसी रोजगारपरक योजनाओं पर ग्रहण लग जाएगी। एफडीआई इन योजनाओं के लिए घातक है।' यह कहना है स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संघर्ष वाहिनी प्रमुख अन्नदा शंकर पाणिग्रह का। बोकारो के सेक्टर–4 स्थित मजदूर मैदान में आयोजित 16वें इस्पातांचल स्वदेशी मेले के समापन दिवस पर हुई एक प्रेसवार्ता को वह संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खुदरा व्यापार में 100 फीसदी विदेशी निवेश से स्वदेशी रोजगार और व्यापार में बाधा आएगी। भारतीय व्यापार बंद होंगे। दूसरी तरफ एयर इंडिया में 49 फीसदी विदेशी पूंजी

निवेश का दरवाजा खोला जाना सरकार का संसदीय परंपरा को धत्ता बताते हुए लिया गया निर्णय है। भारत की संसदीय समिति ने सरकार को यह रिपोर्ट दिया था कि एयर इंडिया में किसी भी प्रकार का विदेशी पूंजी निवेश नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार ने संसदीय समिति की रिपोर्ट की भी अनदेखी की है। उन्होंने कहा– यह आश्चर्यजनक है कि वर्तमान सत्तासीन लोग, जो इन्हीं मुद्दों पर अपने आप को सत्ता पर आसीन हुए, आज पुनः उन्हीं मुद्दों को धत्ता बताते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मौके पर मंच के जिला संयोजक अजय कुमार सिंह ने कहा कि अगर सरकार खुदरा व्यवसाय में एफडीआइ वापस नहीं लेती है या पुनः इस पर विचार नहीं करती है तो स्वदेशी जागरण मंच पूरे देश में चल रहे विरोध को और तेज करेगा। बोकारो सहित सभी जिलों में यह विरोधी स्वर और मजबूत होगा। सरकारी कारगुजारी के खिलाफ व्यापक जनचेतना चलायी जाएगी। प्रेसवार्ता में गुड्डू कुमार, कौशल किशोर, सुजीत कुमार आदि मौजूद थे।

मेडिकल उपकरणों पर मूल्य नियंत्रणः स्वदेशी जागरण मंच

स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कूल्हा संबंधी जैव उपकरण जैसे मेडिकल उपकरणों की 19 श्रेणियों को तत्काल मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत लाने का अनुरोध किया है। ये सारे उपकरण फिलहाल मूल्य विनियमन से बाहर हैं। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मंच ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण स्टेंट के दामों की सीमा के अपने फैसले की समीक्षा कर रही है।

एसजेएम के सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने इस पत्र में कहा कि विदेशी कंपनियों और उसके उद्योग एसोसिएशनों ने मूल्य नियंत्रण को धत्ता बनाने के लिए अपनी लॉबिंग तेज कर दी है और वृद्धिशील नवोन्मेष के नाम पर अपने स्टेंट के लिए ऊंचे दाम की मांग करती हैं। महाजन ने कहा, ''अतएवं, हम आपसे भारतीय लोगों के स्वास्थ्य के अधिकार को बनाए रखने तथा प्राधिकरण को इन विदेशी स्टेंट विनिर्माताओं के दबाव के सामने नहीं झुकने का निर्देश देने का अनुरोध करते हैं।'' पत्र में अस्पतालों द्वारा मरीजों से बहुत अधिक शुल्क वसूलने का मुद्दा भी उठाया गया है।

बचत खाते जैसे हो जायेंगे पीपीएफ

केंद्र सरकार पीपीएफ जैसी सभी छोटी योजनाओं के लिए एक जैसी व्यवस्था करने जा रही है। वित्त विधेयक–2018 के मुताबिक पीपीएफ एक्ट, 1968 खत्म कर दिया जाएगा और सरकार की तरफ से चलाई जा रही 10 प्रमुख बचत योजनाओं के खाते बचत खातों में तब्दील कर दिए जाएंगे। पीपीएफ एक्ट समाप्त हो जाने के बाद उन लोगों को ज्यादा ब्याज का फायदा नहीं मिलेगा, जो नया निवेश करेंगे। सभी नए निवेश गर्वनमेंट सेविंग बैंक एक्ट, 1873 के मुताबिक होंगे। हालांकि उन लोगों को ज्यादा ब्याज मिलता रहेगा, जिन्होंने वित्त विधेयक–2018 लागू होने से पहले से निवेश कर रखा है।

नई व्यवस्था तभी लागू हो पाएगी जब संसद से यह विधेयक पारित हो जाएगा। इन योजनाओं पर पीपीएफ एक्ट खत्म होने का असर पड़ेगा–डाकघर बचत खाते, नेशनल सेविंग मंथली इनकम, नेशनल सेविंग आरडी अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट (1,2,3 और 5 साल), सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम, एनएससी, पीपीएफ और किसान विकास पत्र।

हेल्थ इंडेक्स में केरल का अच्छा प्रदर्शन

स्वास्थ्य में सुधार को लेकर जारी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक केरल राज्य ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। केरल के बाद पंजाब, तमिलनाडु और गुजरात ने अच्छा परफॉर्म किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और ओडिसा

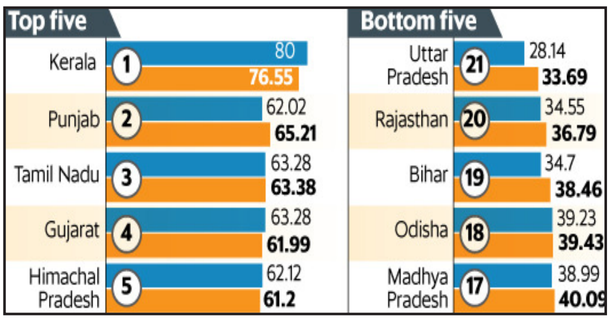

जैसे बड़े राज्यों में हेल्थ को लेकर हालत ज्यादा खराब है।

उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, बिहार और ओडिसा ने हेल्थ इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश ने हेल्थ इंडेक्स के मामले में सबसे खराब परफॉर्म किया है। हालांकि, कुछ समय पहले ही इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। हेल्थ इंडेक्स की सालाना परफॉर्मेंस में झारखंड, जम्मू और कश्मीर ऐसे राज्य हैं जिनकी परफॉर्मेंस में काफी सुधार हुआ है। छोटे राज्यों में मिजोरम के बाद मणिपुर और गोवा ने अच्छा परफॉर्म किया है।

भविष्य की गाड़ियां होंगी इलेक्ट्रिक

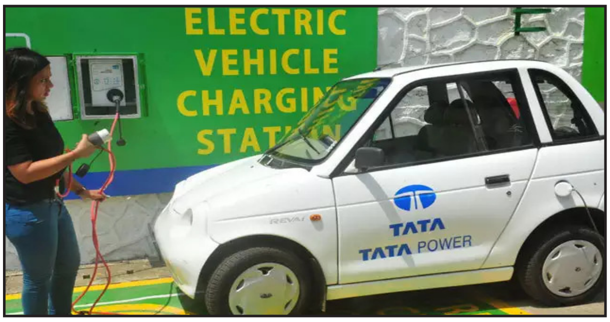

भविष्य की गाड़ियां डीजल–पेट्रोल से नहीं चलेंगी। ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित लगभग सभी कारें इलेक्ट्रिक हैं। पर्यावरण और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये कारें बनाई जा रही हैं। रेनॉल्ट से लेकर मर्सिडीज तक ने कांसेप्ट कार (भविष्य की गाड़ियां) को इलेक्ट्रिक में उतारने की तैयारी की है। इंडिया एक्सपो मार्ट में सबसे पहले मारुति ने हाईब्रिड फ्यूचर एस कांसेप्ट कार एसयूवी को प्रदर्शित किया। हाईब्रिड कार ऑटोमेटिक पायलट गाड़ी होगी। यह ऑफ रोड पर चलने में कारगार होगी। ऑटो एक्सपो में मर्सिडीज ने ईक्यू नाम से इलेक्ट्रिक कांसेप्ट कार उतारी है। 2020 तक यह बाजार में आएगी। इसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर होंगी। यह एक बार चार्ज होने पर 400 किलोमीटर तक चलेगी। इसके मॉडल एस और एक्स भी आएंगे। महिंद्रा ने भी इलेक्ट्रिक कार को बाजार में उतारा। हुंडई, होंडा ने अपने मॉडलों को बेहतर करके नए नाम से उतारा है। इसमें ईंधन की खपत के साथ सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। इलेक्ट्रिक कार पर्यावरण को दूषित होने से बचाएगी।

विश्व के सबसे बोरिंग व इंटरटेनिंग शहर

कई बार अमीरी भी खुश होने की गारंटी नहीं होती। शहरों के मामले में ये बात टाइम आउट मैगजीन की 2018 की लिस्ट में सामने आई है। दुनिया भर के लोगों को बसने

के लिए अट्रैक्ट करने वाले सिंगापुर, दुबई जैसे शहर वहां के रहने वालों के लिए बोरिंग हो गए हैं। मैगजीन ने ऐसे 32 शहरों की लिस्ट जारी की है। आइए जानते हैं कौनसे शहर सबसे बोरिंग हैं।

इस्तानबुलः एंटरटेनमेंट के मामले में इस्तानबुल सबसे पीछे रहा। 32 शहरों में किए सर्वे में इस्तानबुल 32वें स्थान पर रहा। यानी सर्वे में इस्तानबुल को सर्वे में बोरिंग शहर माना गया है। इस सर्वे में करीब 15,000 लोग शामिल हुए थे।

सिंगापुरः 32 शहरों के सर्वे में सिंगापुर 31वें स्थान पर रहा। हालांकि, सर्वे में सिंगापुर को बोरिंग शहर माने जाने पर वहां के लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन सर्वे में सिंगापुर में सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में सबसे आगे माना गया है। टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स में सिर्फ 66 फीसदी लोगों ने माना कि वह सिंगापुर में रहना पसंद करते हैं।

बोस्टनः बोस्टन को 30वें स्थान पर रखा गया है। इसे भी एंटरटेनमेंट और रहने के लिहाज से बोरिंग माना गया है।

दुबईः दुबई को एंटरटेनमेंट के मामले में 29वें स्थान रखा गया है। सर्वे में लोगों ने माना कि दुबई में काम करने के घंटे ज्यादा हैं लेकिन एंटरटेनमेंट ऑप्शन के मामले में यहां ज्यादा विकल्प नहीं है।

शिकागोः शिकागो को सर्वे में सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग शहर माना गया है। शिकागों को 32 शहरों के सर्वे में पहला स्थान दिया गया है। यानी शिकागो को सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग शहर माना गया है।

पोर्टोः पुर्तगाल के पोर्टो शहर को दुसरे स्थान पर रखा गया है। एंटरटेनमेंट के मामले में तीसरे स्थान पर न्यूयॉर्क को रखा गया है। न्यूयॉर्क को फूड, ड्रिंक, कल्चर, फ्रेंडलीनेस, अफॉर्डेबिलिटी, हैप्पीनेस और लाइफ एबिलिटी के मामले में अच्छा स्कोर मिला है।

भारत से ज्यादा इनकम टैक्स लेने वाले देश

आम बजट 2018 से देश का आम करदाता (टैक्सपेयर) इनकम टैक्स स्लैब में बड़ी राहत की उम्मीद कर रहा था। करदाता चाहता था कि कर छूट के दायरे में आने वाली 2.50 लाख की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे देश में टैक्स की अधिकतम सीमा 30 फीसद की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के विकसित देशों में नागरिकों से काफी ज्यादा इनकम टैक्स लिया जाता है।

अमेरिकाः अमेरिका में पर्सनल इनकम टैक्स रेट का मतलब किसी व्यक्तिगत करदाता के लिए 406751 डॉलर से ऊपर की आय पर लगने वाले टॉप मार्जिनल फेडरल टैक्स रेट से होता है। करदाता पर अतिरिक्त राज्य टैक्स भी लग सकता है। अमेरिका में पर्सनल इनकम टैक्स रेट 39.60 फीसद है।

चीनः चीन में किसी भी व्यक्ति पर लगने वाला टैक्स उसकी आय की श्रेणी के आधार पर तय किया जाता है। किसी भी व्यक्ति पर लगाया जाने वाला पर्सनल इनकम टैक्स रेट 45 फीसद है।

जापानः जापान में पर्मानेंट रेजिडेंट टैक्सपेयर पर वर्ल्डवाइड इनकम के आधार पर टैक्स लगाया जाता है। जापान में पर्सनल इनकम टैक्स रेट 55.95 फीसदी है।

जर्मनीः सभी रेजिडेंट व्यक्तियों पर 8820 यूरो या उससे ज्यादा की वर्ल्डवाइड इनकम पर टैक्स लगाया जाता है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के मुताबिक जर्मनी में पर्सनल इनकम टैक्स रेट 47.50 फीसद है।

इटलीः इटली में करदाता पर नेशनल इनकम टैक्स या पर्सनल इनकम टैक्स, रीजनल इनकम टैक्स और म्युनिसिपल इनकम टैक्स जैसे आयकर लगते हैं। इटली में पर्सनल इनकम टैक्स रेट 48.80 फीसद के स्तर पर है।

संविधान में नहीं है 'बजट' शब्द का जिक्र

वित्तमंत्री हर साल फरवरी के महीने में देश का आम बजट पेश करते हैं। पहले आम बजट फरवरी के अंतिम दिन यानी 28 या 29 फरवरी को आता था। 2017 से आम बजट 1 फरवरी को पेश करने की परंपरा शुरु हुई। लेकिन यह जानकर आपको हैरानी होगी कि देश के संविधान में 'बजट' शब्द का जिक्र ही नहीं है। दरअसल संविधान में कहा गया है कि सरकार हर साल संसद के समक्ष अपना 'वार्षिक वित्तीय विवरण' पेश करेगी। इसके ही लोकप्रिय भाषा में बजट कहा जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र सरकार को हर साल संसद के दोनों सदनों के समक्ष सालाना वित्तीय विवरण रखना चाहिए। वार्षिक वित्तीय विवरण में तीन अलग अलग भागों में सरकार की आमदनी और खर्च का ब्यौरा होता है। ये तीन हैंः (1) भारत की संचित निधि (2) भारत की आपात निधि (3) लोक लेखा। वैसे संसद के वित्तीय कामकाज में मुख्यतौर पर आम बजट, अनुदान की मांगें, लेखानुदान, अनुदान की पूरक मांगें, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक हैं।

पहले केंद्र सरकार का बजट दो हिस्सों में संसद में पेश किया जाता था। रेल बजट व आम बजट। रेल बजट सामान्यतः आम बजट से दो दिन पूर्व पेश किया जाता था। हालांकि पिछली बार से सरकार ने रेल बजट को आम बजट में ही समाहित कर दिया है। इस तरह अब अलग से रेल

बजट पेश नहीं होता है। अंतिम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री सुरेश प्रभु हैं। संविधान के प्रावधानों के अनुरूप 31 मार्च से पहले अनुदान की मांगें पारित हो जानी चाहिए ताकि नये वित्त वर्ष में संचित निधि से धन निकालने में दिक्कत न आये। इसके अलावा आम बजट में कर प्रस्ताव पेश होने के 75 दिन के भीतर वित्त विधेयक पारित हो जाना चाहिए।

कैसे मिलेगा मोदी केयर का लाभ

यूं तो जेटली ने इस बार के बजट में कई तरह की स्कीमों का एलान किया। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा मोदी केयर या प्रधानमंत्री हेल्थ इन्श्योरेंस स्कीम या आयुष्मान स्कीम की हो रही है। इस स्कीम को लेकर अब तक सरकार और मीडिया के लेवल पर कई तरह की जानकारी छनकर सामने आ चुकी हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आखिर किस तरह इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए क्या-क्या शर्तें होंगी। जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा उन्हें कुछ प्रीमियम देना होगा या नहीं। साथ ही इसमें सरकार की क्या भूमिका होगा और लोगों को कैसे इलाज मिलेगा। इससे जुड़ने वाले हर परिवार को 5 लाख रुपए का कवर मिलेगा। मतलब एक परिवार एक साल में इस स्कीम के जरिए 5 लाख रुपए का इलाज करा सकता है। बजट भाषण के मुताबिक, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले करीब 10 करोड़ परिवारों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक, सरकार इसके लिए प्रीमियम के तौर पर कोई भी राशि नहीं वसूलेगी।

सूत्रों के मुताबिक, मरीज का आधार नंबर ही उसका कार्ड होगा। सरकार कुछ अस्पतालों को इस योजना से जोड़ेगी। मरीज को उन अस्पतालों में जाकर अपना आधार नंबर बताना होगा और इलाज मिल जाएगा।

बढ़ सकती है महंगाई

रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर उर्जित पटेल की अगुवाई में मौद्रिक नीति समिति ने घोषित ऋण एवं मौद्रिक नीति बयान में महंगाई को लेकर चिंता जताई है। इसे ध्यान में रखकर नीतिगत ब्याज दरों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक के बयान में कहा गया है कि छह कारणों से महंगाई को लेकर चिंता है।

एमएसपी से मिलेगी हवा: रिजर्व बैंक का मानना है कि आगामी खरीफ मौसम से अधिसूचित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लागत मूल्य की तुलना में डेढ़ गुना किये जाने से महंगाई बढ़ सकती है। नीति के मुताबिक आम बजट में 2018-19 से खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति में बदलाव से महंगाई बढ़ सकती है। 1 फरवरी को पेश बजट में खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को लागत मूल्य की तुलना में कम से कम डेढ़ गुना किए जाने की घोषणा की गई है।

सातवां वेतन आयोग: केंद्रीय बैंक की महंगाई को लेकर चिंता बढ़ाने वाले कारकों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें भी हैं। बैंक का कहना है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों ने आवास भत्ता (एचआरए) बढ़ा दिया है। सातवां वेतन आयोग केंद्र सरकार ने पिछले साल जनवरी से लागू किया है।

कच्चे तेल के ऊंचे दाम: केंद्रीय बैंक कहा है कि वैश्विक विकास में तेजी से कच्चे तेल और जिंसों के बढ़ते दाम भी घरेलू बाजार में कीमतों पर असर डाल सकते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से घरेलू बाजार में डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं। पेट्रोल के दाम भी रिकॉर्ड के काफी करीब पहुंच चुका है।

सीमा शुल्क और राजकोषीय घाटा: अन्य कारणों में बजट में कई सामानों पर सीमा शुल्क बढ़ाने से भी महंगाई बढ़ने की आशंका है। बजट में वित्तीय घाटे का लक्ष्य पूरा नहीं होने के संकेतों से भी महंगाई को हवा मिलने की आशंका है। चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान में वित्तीय घाटा 3.2 प्रतिशत के तय लक्ष्य की तुलना में 3.5 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष में 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।

इनका भी रहेगा डर: बैंक ने कहा है कि घरेलू वित्तीय विकास और विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की मौद्रिक नीति के कठोर करने के कारण विदेशी निवेशकों का विश्वास डगमगा सकता है। बयान में खुदरा महंगाई को मध्यावधि में चार प्रतिशत (दो प्रतिशत कम-ज्यादा तक) रखने की प्रतिबद्धता दुहराई गई है। हालांकि, उसमें यह भी कहा गया है जनवरी-मार्च 2018 की तिमाही में महंगाई दर 5.1 प्रतिशत पर पहुंच सकती है।

स्टेट बैंक ने 20 हजार करोड़ बट्टे खाते में डाले

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने 2016-17 में 20,339 करोड़ रुपये के फंसे कर्ज को बट्टे खाते में डाल दिया। यह सरकारी बैंकों में सबसे अधिक राशि है जो बट्टे

खाते में डाली गई है। इस प्रकार 2016–17 में बैंकों के बट्टे खाते में कुल मिलाकर 81,683 करोड़ रुपये की राशि डाली गई। यह आंकड़े तब के हैं जब भारतीय स्टेट बैंक में उसके सहयोगी बैंकों का विलय नहीं किया गया था। सरकारी आंकड़े दिखाते हैं कि वित्त वर्ष 2012–13 में सरकारी बैंकों का कुल बट्टा खाता 27,231 करोड़ रुपये था।

इस प्रकार पांच साल की अवधि में यह राशि तीन गुना बढ़ गई है। वित्त वर्ष 2013–14 में सरकारी बैंकों ने 34,409 करोड़ रुपये के फंसे कर्ज को बट्टे खाते डाला था। वित्त वर्ष 2014–15 में यह राशि 49,018 करोड़ रुपये, 2015–16 में 57,585 करोड़ रुपये और मार्च 2017 में समाप्त हुए वित्त वर्ष में 81,683 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

स्टेट बैंक के अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने भी 2016–17 में 9,205 करोड़ रुपये बट्टे खाते डाले हैं। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने 7,346 करोड़ रुपये, केनरा बैंक ने 5,545 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 4,348 करोड़ रुपये बट्टे खाते डाले हैं। चालू वित्त वर्ष में सितंबर छमाही तक सरकारी बैंकों ने 53,625 करोड़ रुपये के कर्ज को बट्टे खाते डाला है।

अब भी जारी है पुराने नोटों की गिनती

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 15 महीने पहले नोटबंदी के ऐलान के बाद जो उच्च मूल्य के मुद्रा 500 और 1000 रूपये के नोट जमा कराए गए थे उनकी गिनती अभी भी जारी है। ताकि, उनकी संख्या के सही आकलन और सटीकता का पता लगाया जा सके। सेंट्रल बैंक के मुताबिक,

यह काम काफी तेज़ी के साथ चल रहा है।

पीटीआई संवाददाता की तरफ से लगाई गए आरटीआई आवेदन के जवाब में आरबीआई ने कहा– कुछ विशेष बैंकों के नोट्स को संख्या और सटीकता के लिहाज गिनती की जा रही है और इसके पूरा होने के बाद ही इस बारे में जानकारी साझा की जा सकेगी।

इसमें आगे कहा गया है कि अनुमानित विशेष नोट 30 जून 2017 तक 15.28 ट्रिलियन (लाख करोड़) रुपये प्राप्त हुए। जब यह पूछा गया कि कोई निश्चिम समय–सीमा बताएं जिसमें पुराने नोटों की गिनती पूरी हो जाए। इसके जवाब में आरबीआई ने कहा कि नोटों की गिनती का काम काफी तेज़ी के साथ किया जा रहा है।

रेलवे 13 हजार गैरहाजिर कर्मचारियों की करेगा छंटनी

भारतीय रेलवे ने 13,000 से ज्यादा ऐसे कर्मचारियों की पहचान की है जो लंबे समय से अनाधिकृत छुट्टियों पर हैं और उनको नौकरी से निकालने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। रेलवे ने ऑर्गेनाइजेशन का प्रदर्शन बेहतर करने और ईमानदार व मेहनती कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया था। यह कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा है।

रेलवे के बयान में कहा गया है कि रेलवे के विभिन्न प्रतिष्ठानों में लंबे समय से गैहाजिर कर्मचारियों की पहचान करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के परिणाम में रेलवे ने अपने लगभग 13 लाख कर्मचारियों में से 13 हजार से भी अधिक ऐसे कर्मचारियों की पहचान की है जो लंबे समय से गैरहाजिर हैं।

रेलवे ने इन गैरहाजिर कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के लिए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। रेलवे ने सभी अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को उचित प्रक्रिया पर अमल के बाद कर्मचारियों की सूची से इनका नाम हटाने का निर्देश दिया है। ❑❑

स्वदेशी अपनाओ - देश समद्ध बनाओ

वस्तु	स्वदेशी उत्पादन-प्रयोग करें
नहाने का साबुन	गोदरेज, संतूर, निरमा, स्वस्तिक, मैसूर सँडल, विप्रो–शिकाकाई, फ्रेश, अफगाण, कुटीर, होमाकोल, प्रिमियम, मीरा, मेडिमिक्स, पितांबरी, विमल, चंद्रिका, गंगा, सिंथाल, वनश्री, सर्वोदय, नीमा, अनुरा, तथा लघु–कुटीर उद्योग के अन्य स्थानीय उत्पादन
कपड़े धोने का साबुन	स्वस्तिक, ससा, प्लस, निरमा, ॲक्टो, विमल, हीपोलीन, डेट, पितांबरी, बी.बी., फेना, उजाला, ईज़ी, घड़ी, जेंटिल, मंजुला, अनुरा, अन्य स्थानिक उत्पादन, अन्य लघु–कुटीर उद्योग के अन्य स्थानीय उत्पादन
सौंदर्य प्रसाधन औषधि	टिप्स एण्ड टोज, श्रंगार, सिंथॉल, संतूर, इमामी, अफगाण, बोरोप्लस, तुलसी, वीको टर्मरिक, अर्निका, हेयर एण्ड केयर, हिमानी, पॅराशूट, डॅन्ड्रफ सोल्युशन, हिमताज, सिल्केशा, नाईल, फेम, बलसारा, जेके, डाबर झंडू, सांडू, बेद्यनाथ, हिमालय, भास्कर, तन्वी, बोरोलीन, केराफेड, बजाज सेवाश्रम, प्रकाश, कोकोराज, प्रिमियम, मूव, क्रैक क्रीम, आयुर, पार्क एवेन्यू, कासवछाप नेचर इसेस और लघु–कुटीर उद्योग के अन्य स्थानीय उत्पादन
टुथपेस्ट दंतमंजन टुथब्रश	बबूल, प्रॅामिस, विको, ओरा, अमर, अँकर, डाबर, बंदर छाप, टु जेल, चॉईस, मिसवाक, अजय, हर्बोडेंट, अजंता, गरवारे ब्रश, क्लासिक, ईगल, दंतपोला, बंदर छाप, वैद्यनाथ, युवराज, इमामी तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
दाढ़ी का साबुन ब्लेड्स	गॅादरेज, अफगाण, इमामी, सुपर, स्वदेशी, सुपरमैक्स, अशोक, वी–जॉन, टोपाज, पनाना, प्रीमियम, पार्क एवेन्यू, लेझर, विद्युत, जे.के. तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
बिस्कीट चॉकलेट दुग्ध उत्पादन ब्रेड	साठे, बेकमेन, मोनॅको, क्रेकजैक, गिट्स, शालीमार, पैरी, रावलगांव, निलगिरी, क्लासिक, अमूल, न्यूट्रामूल, मॉन्जीनीज, आरे, कॅमको, सम्राट, रॉयल, विजया, इंडाना, सफल, एशियन, विव्स ब्रेड, वेरका, सागर, सपन, प्रिया गोल्ड, न्यूट्रीन, शांग्रिला, चॅम्पियन, ॲम्प्रो, पार्ले, तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
चाय कॉफी	गिरनार, हसमुख, टाटा टी, आसाम टी, सोसायटी, सपट (इस्टंट), डंकन, बह्मपुत्र, एम.आर., शन, टिपस, इंडीया, अशोक, तेज, टाटा कॅफे, कन्सोलिडेटेट कॅफे, टाटा–टेटली और अन्य स्थानीय उत्पादन
शीतपेय शरबत, चटनी अचार, मुरब्बा	एनर्जी, सोसयो, कॅम्पाकोला, गुरूजी, ओन्जुस, जाम्पिन, नीरो, पिंगो, फ्रूटी, आस्वाद, डाबर, माला, रॉजर्स, रसना, हमदर्द, मैप्रो, रेनबो, कॅल्वर्ट, सीटेम्ब्लिका, रूह–आफजा, जय गजानन, हल्दीराम, गोकुल, बीकानेर, वेकफील्ड, नोगा, प्रिया, अशोक, मदर्स रेसेपी, उमा, एच.पी.एम.सी उत्पाद, हिम तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
पीने का पानी	बिसलेरी, बैली, नॅचरल, अन्य स्थानीय उत्पादन
आईस्क्रीम	दिनशॉ, जॉय, वाडीलाल, श्रीराम, पेस्तनजी, नेचर वर्ल्ड, गोकूल, अमूल, हिमालय, निरूला, पेरीना, मदर डेयरी, आरे, विंडी, हॅव मोर, वेरका तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
खाद्यतेल खाद्यपदार्थ	सनफ्लावर, मारूति, पोस्टमैन, धारा, रॉकेट, गिन्नी, स्वीकार, कॉरनेला, सनड्राप, रथ, मोहन, उमंग, विजया, सपन, पॅराशूट, अशोक, सफोला, कोहिनूर, मधुर, इंजन, गगन, अमत, वनस्पति, रामदेव, एमडीएच, एवरेस्ट, बेडेकर, कुबल, डाबर, सहकार, लिज्जत, गणेश, शक्तिभोग आटा, टाटा नमक, एम.टी.आर. तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
विद्युत उपकरण गहोपयोगी वस्तु	विडियोकॉन, बी.पी.एल, ओनिडा, सलोरा, ईटीएण्डटी, टी–सीरीज, नेल्को, वेस्टर्न, अपट्रॉन, केल्ट्रान, कॉस्मिक, टीवीएस, गोदरेज, क्राउन, बजाज, उषा, पोलर, एँकर, सूर्या, ओरिएन्ट, सिन्नी, टूल्लू, क्रॅाम्पटन, रवी, जय शंकर, कैलाश, श्रीराम, लायड्स, ब्लू स्टार, व्होल्टास, कूल होम, खेतान, एव्हरेडी, जीप, नोविनो, ॲम्प्रो, निर्लेप, इलाईट, अंजली, जयको, सुमीत, बंगाल, मैसूर, हॉकिन्स, प्रेस्टीज, महाराजा, जयपान, प्रेशर कुकर तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
घड़ियां	टाइटन, अजन्ता, एचएमटी, मैक्सिमा, आल्विन,
लेखन सामग्री	ज़ीफ्लो, विल्सन, कैम्लिन, रेव्हलॉन, रोटोमॅक, सेलो, स्टिक, चंद्रा, मोंटेक्स, कैमल, बिट्टू, स्टिक, प्लेटो, कोलो, त्रिवेणी, फ्लोरा, अप्सरा, नटराज, हिंदुस्तान, ओमेगा, लोटस, कैमे, लिंक तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
जूते, चप्पल पॉलिश	लखानी, लिबर्टी स्टैन्डर्ड, एक्शन, पैरागॉन, फ्लॅश, करोना, वेलकम, रेक्सोना, रिलैक्सो, लोटस, रेड–टेप, फिनिक्स, वायकिंग, बिल्ली, कार्नोबा, किवी शू पॉलिश, फ्लेक्स, बुडलॅनड तथा अन्य स्थानीय उत्पादन
तैयार कपड़े	पीटर इंग्लैंड, व्हॅन हुसेन, ॲलेन सॉलीए, लुई फिलिप, कलरप्लस, मफतलाल, ट्रेंड, केम्ब्रिज, डबल बुल, झोडिएक, अरविंद डेनिम, डॉन, प्रोलीन, टीटी, लक्स, अमूल, वीआईपी, रूपा, रेमण्ड, पार्क एवेन्यू, अल्टिमो, न्यूपोर्ट, किलर, फ्लाईंग मशीन, डयूक्स, कोलकाता, लुधियाना तथा तिरुपुर के सभी हौजरी सहित अन्य स्थानीय उत्पादन